साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 4 अंक 34 प्रति सोमवार इंदौर, 28 फरवरी से 6 मार्च 2011 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

आरएसएस को बदनाम करने और मुस्लिम वोट बैंक कबाड़ने में

आतंक को आश्रय, शत्रु को प्रश्रय और जग हंसाई

सीबीआई बन गया कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन, सत्ता जागीर है

केन्द्रीय शासन की जांच एजेन्सी, सत्ताधीश जालसाज कांग्रेसी डकैतों की घरेलु जांच एजेन्सी बन गई है। अपने भ्रष्टाचार के कुकर्मों को दबाने, भाजपा की पैतृक पार्टी को बदनाम करने और भापा पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने केन्द्रीय जांच ब्यूरों का वास्तविकता में कांग्रेस जांच ब्यूरों बना दिया है। 6 वर्ष का सीबीआई का इतिहास गवाह है।

हर आतंकवादी घटना में जिसे स्वयं कांग्रेस संरक्षण देकर करवाती आ रही है। कांग्रेसी डकैतो का इतिहास रहा है, जब-जब वह अपने भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिर जाती है, तब-तब देश में कहीं न कहीं आतंकवादी हमले करवा कर मिडिया, जनता और विपक्षी दलों का ध्यान परिवर्तन कर अपने कुकर्मों को दबा देती है। फिर ये कांग्रेसी श्वान सोनिया से लेकर चीट अंबर तक अपने सत्ता में रहने का दुरुपयोग कर कांग्रेस ब्यूरों ऑफ इंवेस्टीगेशन दबाव बना कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बदनाम करने के लिए उनके साधु संतो, पदाधिकारियों की पकड़ धकड़ कर जेलों में उनको साथ भयानक मारपीट कर, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करवा प्रताड़ना देकर अपने मनमाफिक ब्यान दिलवाते है। और जानबूझकर उसे धन देकर मिडिया में जारी करवा कर एक तरफ तो ये जालसाज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो राष्ट्रीय भावना और कानून का पालन करने वाले होते है उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते है। दूसरी और वास्तविक आतंकवादियों जो सभी मुस्लिम होते है बचाने का षड़यंत्र मात्र हिन्दुओं को बदना मकरने और शुद्धतः मुस्लिम वोट बैंक कबाड़ने और मुस्लिम समुदाय की निगाह में उनकी वास्तविक सर परस्ती दिखाना हे। जबकि कांग्रेसी षड़यंत्री डकैतों की इस चाल में कम से कम यूपी का मुसलमान न केवल समझता है वरन उसने न केवल युपी और बिहार से कांग्रेसियों का सूपड़ा साफ ही कर दिया और जब से कांग्रेस युपी से बाहर हुई है तबसे अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ जैसे कर्फ्यू की आग में जलने वाले शहरों में गैर मुस्लिम सरकारों के रहते चलते चाहे वह भाजपा की हो, सपा या बसपा की रही है। यूपी जो 1947 तक 1985 तक दंगों की आज झुलसता रहता था बिल्कुल ही दंगे बंद हो गए। वैसे भी कांग्रेस अंग्रेजों की पार्टी है। विरासत में कांग्रेस को जाते-जाते देकर गई थी कि हमने फूट डालों राजकरों की नीति पर 300 वर्ष राज्य किया है। तुम भी हिन्दुओं और मुस्लमानों को लड़वाकर ऐसे ही राज करों कांग्रेस उसी नीति का पालन करते हुए हिन्दुओं को दबाने और मुस्लिमों को संरक्षण देने की नीति पर अपनी सत्ता का स्थायित्व तलाशती है।इन सब शतरंजी चालों के विपरीत कांग्रेस की यह चाल न केवल राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दशब्दियों को सफल रही वरन मुस्लमान भी शिक्षित प्रदेशों को उन्हें अपना सब कुछ मानता है। जबकि जिन्हें हम पिछड़ा हुआ प्रदेश मानते है। वो सब जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बिहार, उप्र, मप्र इन के चंगुल से बाहर आ चुका है। और इन षड़यंत्रकारियों से बचकर भी चलता है वरन इन हरामखोर, जालसाज कांग्रेसी डकैतों को वोट भी नहीं देता।

राष्ट्र में पिछले साठ वर्षों में इस चाल में सफल रहे हो पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी हर चाल उसी के गले की हड्डी बन गई। जैसा कि अभी तत्काल में हुआ, कि इंडेश गोस्वामी स्वामी असीमानंद, कर्न पुरोहित, प्रज्ञा आदि को दबाने, समझौता ब्लास्ट आदि ने जोड़ कर सीबीआई ने झूठे ही उसने यह कहा, वहकहा कर के पूरे मिडिया में खबरे उड़ा कर स्वयं न केवल पाकिस्तान के आतंकवादियों को सरपरस्ती की वरन उल्टे ही पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को बुलाकर उल्टे ही फटकार दिया। इससे कुल मिलाकर भारत सरकार की न केवल पाकिस्तान ने ही धज्जियां बिखेर दी वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जगह साई हुई सो अलग दूसरी तरफ कर्नल पुरोहित को लपेअ कर अपनी ही सेना की इन हरामखोरों ने विश्वसनीयता खोई और दूसरी तरफ सेना के अधिककारियों का मनोबल भी तोड़ा पूरे भारत में।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

डाके डालकर, कांग्रेसियों के घड़ियाली आंसू

कमीशनखोरों का चिंतनीय नाटक महंगाई पर

पूरे देश में चारों तरफ तेज से महंगाई बढ़ने का केन्द्र के सत्ताधीश कांग्रेसी गिरोह के डकैत सरदार मनमोहन मंत्री प्रणव मुखर्जी और परमधूर्त कृषि मंत्री शरद पंवार स्वयं 19 प्रतिशत से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर चिंता होने का नाटक दिखा रहे है। यथार्थ में स्वयं ही मुकेश अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम को लाभ पहुंचाने के लिए पिछले 5 वर्षों में सभी सरकारी तेल कंपनियों को डुबोने और बर्बाद करने जतना को लूटने के लिए ही अनुदान देने का नाटक, क्योंकि अनुदान भी जनता का ही पैसा है, जो जनता से वसूला गया है। कांग्रेसी डकैतों के बाप की जागीर नहीं यास्विस बैंकों में जमा अरबों करोड़ से नहीं दिया जाता है। किया जाता है। अनुदान समाप्त करने के नाटक के नाम बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि कर रु.43 का पेट्रोल रु. 60/- प्रति लीटर कर दिया ताकि रिलायंस इंडस्ट्री को उसके पेट्रोलियम पदार्थों को खुले में सरकारी कंपनियों से कम रेट पर बेंचने का मौका मिले।

दूसरी और देश की सत्ता में नामांकित प्रधान मंत्री और कांग्रेसी डकैतों के सरदार मन मोहनसिंग व उनका गिरोह महंगाई पर घड़ियाई आंसु बहाता हुआ कई बैठके कर

अंबानी के फायदे और मोटे कमीशन ने बढ़ाई पेट्रोल की कीमते

चुका है। पर सारे हरामखोर, धूर्त गिद्ध, महंगाई के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई भी गिद्ध बोलने को न केवल तैयार नहीं वरन वास्तविकता में कोई भी हदय से नहीं चाहता कि महंगाई दूर हो।

जन.10 से जन.11 तक पूरे वर्ष भर पेट्रोल की कीमतें हर महीने किसी न किसी बहाने बढ़ाई जाती रही है। और ये धूर्त इस वर्ष के अंत तक 70 से 80 रु. प्रति लीटर और सन 2014 तक रु. 100/-प्रति लीटर पेट्रोल और रु. 60 प्रति लीटर डीजल बेचेंगे। वर्तमान में 65 रु. पेट्रोल और डीजल 44 रु. प्रति लीटर कर ही दिया है। स्वाभाविक है बाजार में हर वस्तु की कीमतें इसी अनुपात में बढ़ जाएंगी ये सारा खेल रिलायंस पेट्रोलियम की एशिया की सबसे बड़ी रिफायनरी के माल को बेंचने की प्राथमिक जरुरत है। न ही शासकीय पेट्रोलियम कं. बीपीसी एल, एचपीसीएल आईओसी को कोई घाटा हो रहा है। जब शासकीय कंपनियां है। तो घाटा मुनाफा तो सब सरकार का है। हाथ-तौबा के केवल अरबों करोड़ के कमीशन और लाभ की है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

आम जनता को पेट्रोल पर पड़ रहा है रुपए 100 प्रति लीटर

सबसे बड़ा मिलावटिया रिलायंस पेट्रोलियम

नेपस्था, साल्वेंट पूरे देश में पेट्रोल पंप रिलायंस से खरीदकर ही मिलाते हैं

म.प्र. में वर्तमान में पेट्रोल रुपए 62/- से रुपए 65/- प्रतिलीटर बिक रहा है जो पूरे देश में सबसे महंगा है। इसके विपरीत इस पेट्रोल की कीमत जनता को रुपए 100/- प्रति लीटर पड़ती है। क्योंकि न्यूनतम 10% से 40-40% तक कम नापा जाता है। साथ ही 25 से 40% इसमें नेपस्था, साल्वेंट, मिट्टी का तेल व अन्य पदार्थ मिलाकर बेचा जाता है। जिसकी कीमत रुपए 10 से 22/- प्रति लीटर तक होती है। पूरे देश में नेपस्था, साल्वेंट, सचएसडी जैसे तरह सस्ते पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकांश बिक्री रिलायंस पेट्रोलियम के जामनगर गुजरात से की जाती है। रिलायंस पेट्रोलियम के पूरे देश में फैलाये गये पेट्रोल पंपों पर भी यही साल्वेंट, हैक्सीन, नेपस्था, एचएसडी युक्त पेट्रोल ही बेचा जा रहा था। जिसकी पूरी जानकारी म.प्र. के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के हर जिलाअधिकारियों के साथ खाद्य निरीक्षकों को भी थी और है। गैस पंपों पर जहां सीएनजी, एलपीजी बेची जाती है उसमें भी न केवल कार्बन डाइआक्साइड को विखंडित कर कार्बन मोनाआक्साइड और अन्य कार्बोनिक गैसेज मिलाकर लीटर से बेंची जा रही है। पूरे देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों यथा पेट्रोल और डीजल के तो नमूने भी लिये जा सकते हैं में सीएनजी, एलपीजी के तो नमूने लेने की भी व्यवस्था ही नहीं है, पूरे देश में। दूसरी ओर इंडियन आइल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के क्षेत्रीय विपणन प्रबंधकों को भी मिलावट और कम नापने के संबंध में जो शिकायतें मिलती भी है तो भी ये सब को पंप मालिकों के साथ मिलकर अपना हिस्सा डकार कर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास के साथ ही पूरे प्रदेश और देश में जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी से लेकर निरीक्षकों तक का, वही नाप-तौल विभाग के जिलाधिकारी और निरीक्षकों का महीना बंधा होने के कारण ये सारे हरामखोरों की फौज कार्यवाही की तो दूर देखने-झांकने भी नहीं जाती। अचानक जांच करने, नमूने लेना भी औपचारिकतावश वर्ष्ा भर में एक-दो बार, पेट्रोल और डीजल पंप मालिकों को विश्वास और बड़े अनुनय विनय के बाद लेकर सरकार और जनता पर एहसान करते हैं। परन्तु ये सारे पेट्रोल-डीजल के नमूने लेना केवल जनता की आंखों में धूल झोंकना और दिखावे की कार्यवाही कर स्वयं शासन को और जनता को भ्रमित करना है। क्योंकि म.प्र. शासन की अपनी कोई प्रयोगशाला ही हनीं जिसमें उस पेट्रोल और डीजल के नमूने की जांच कर उसकी शुद्धता जांची जा सके। वे सारी प्रयोगशलाएं आईओसी, एचपी, बीपीसीएल की प्रयोगशाला में ही भेजे जाते हैं, जहां आंख मींचकर सारे नमूने में आधा मिट्टी का तेल मिलाकर इंदौर के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने भेजे, तो भी शुद्धता की रिपोर्ट ही आई बाकी तो कुछ कहना निष्कर्षहीन ही होगा।

अर्थात पेट्रोल-डीजल, मिट्टी तेल, एलपीजी, सीएनजी, आदि

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भ्रष्ट निकंमों की सरकार, कैसे करे कार्रवाई ?

99% आईएएस, आईपीएस, आईएफएस भ्रष्ट

सब जुटे है, वसुली में, जन-धन, संपत्तियों और कानूनों की आड़ में...

हमारा देश, सोने की चिड़िया कल भी था, अभी भी है, और कल भी रहेगा। आखिर सोना उगलने वाली धरती, कल-कल करता नदियों में बहता जल, उर्वरा भूमि शीतोष्ण जलवायु, अधिकांश मौसम निश्चित, 125 करोड़ मेहतनकश आबादी फिर भी हमारे सत्ताधिशों के हाथ कभी विश्व बैंक से कभी एशिया विकास बैंक से ऋण की भीख मांगते, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे छोटे राष्ट्रों से सहायता के लिए हाथ फैलाते, आखिर क्यों? हम भिखारी है। हमारे राष्ट्र के गेंहू, दाल, चावल, घी, तेल, शकर से लेकर लोहा, तांबा, अभ्रक से लेकर क्रोमोजाइट, तक हम निर्यात करते है। थोरियम, युरेनियम, प्लेअिनम तक के हम मालिक है। इकसे विपरीत हम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी है। इसके लिए मात्र जिम्मेदार है, तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण हम दाता होने के बाद भी है तो भिखारी ।

कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक सब आकंड डूबे है। यहां पर शीर्ष से लेकर अंतिम घोर जातों की पंचायतों तक सब बस बटोरने में लगे है। महाबेशर्माई और ढीठ पन से। किसी को भी किसी से डर नहीं है। 99 प्रतिशत आसानी से अपने भ्रष्टाचार के कारनामज्ञों वकज्ञो अंजाम देकर और धन बटोर कर आसानी से निकल लेते है।

1 प्रतिशत भी भ्रष्ट नेता, मंत्री, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस, एसएएस भी मुश्किल से पकड़े जाते है। इसके साथ ही सच यह भी है कि सत्ता में बैठा न केवल अधिकारी, निरीक्षक, कर्मचारी है तो सभी न केवल भ्रष्ट सभी जुठे है। वसूली और भ्रष्टाचार में, तो कौन किसकी कहे, जहां तक एजेंसियों का सवाल है, तो वहां कोई देव पुरुष तो नहीं है। तो वहां भी साधारण मनुष्य जिसको मौका मिलते है। हर कोई उसे मुनाता और वसूली करता है।

इस संदर्भ में प्रदेश में ही ले। अधिकांश आईएबएस अर्थात इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारियों को ही ले। अधिकांश अधिकारी अरबों रु.से हजारों, करोड़ो का मालिक है। उन पर आयकर की चपेअ में जो अधिकारी आए, उनमें अरविन्द और टीनू जोशी को ही लें। सैकड़ों करोड़ों की संपत्तियों और आयकर के सिकंजा कसने के महीनों बाद प्रदेश सरकार उन पर कार्रवाई कर पाई। डॉ. राजेश राजौरा की मात्र रु. 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर आयकर ने सिकंजा कसा पर प्रदेश सरकार ने उस पर से आंख मींच रखी है। मप्र ओ केन्द्रीय विकास निगम के पूर्व प्रबंध संचालक एमपी राजन और सुधिरंजन मोहंती पर रु.2200 करोड़ के केएल विभाग के घोटाले पर भी भाजपाई सरकार ईमानदारी का ही ढ्ढोस वैसे भी पीएस, अपराध रोकने की अपेक्षा अपराध हो जाने के बाद अपराधियों से वसूली में विश्वास रखते है। इन्हीं के संरक्षण में जुआ, सट्टा, वैश्यावृति, अवैध कारोबार चलते है। जिनसे महीना वसूली होती रहती है। जो कि मालवा में छोटे-छोटे शहरों में भी करोड़ों रु. प्रति माह में होती हे। इंदौर मे ही एसएसपी प्रणाली लागू होने के बाद हत्याओं, लूट, डकैतियों, (शेष पृष्ठ 3 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

अंधे पीसें-कुत्ते खायें

पूरे विश्व में राष्ट्रों में उनके प्रदेशों में और प्रदेश नगरों में शासक रूपी अंधे जनता के धन को दिखावे के लिए जन हित में पीसते हैं। सत्ता में बैठे सरकार के सरकारी श्वानों रूपी कार्यों को संपन्न करने के लिए बैठे वे सारे अधिकारी, कर्मचारी खा जाते हैं।

यह सत्य समय माया ने विश्व की जनता के हित में अपने प्रादुर्भाव से ही प्रगट करना प्रारंभ कर दिये थे, उस समय से वर्तमान तक स्पष्ट सत्य पाठकों को हजम नहीं हो रहा था, जबकि वास्तविकता में जो प्रगट किया जा रहा था वह जन के मन की भावना ही थी; तब भी थी और वर्तमान में भी है। यदि ऐसा नहीं होता तो, टयुनीशिया और मिस्र में जो हो रहा है वह नहीं होता जिसकी आग एशिया में विशेष रूप से भारत में भी भड़कने और फैलने लगी है। भारत के भी 60 नगरों में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारे बुलंद किये गये।

जनता से बटोरा गया धन, शासकों के हाथ आता है, दिखावे के लिए जनहितों के नाम पर वे शासक सरकार में बैठे अधिकारियों को जनहितार्थ बांटते हैं। परन्तु वे उस धन को कागजों रूपी खेतों में आंकड़ों, संख्याओं और शब्दों की खेती कर स्वयं ही हजम कर जाते हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए उन आंकड़ों, संख्याओं और शब्दों रूपी फसल दिखाकर स्वयं मिट्ठू मियां स्वयं खुश होते हैं और दशाब्दियों से जनता को खुश करते रहे हैं। पर युग परिवर्तन के इस मोड़ पर जनता ने कागजों के खेतों पर आंकड़ों की फसल से आभासी भूख को मिटाने की इस क्रीड़ा को समझ कर वास्तविक उत्पादन, सुख संपन्नता के लिए क्रांति करना शुरू कर दिया है।

इसके विपरीत भारत के केंद्रीय शासन के नयन सुखों ने अभी भी अपनी जिद् नहीं छोड़ी है। दिमाग पर लूट के भूत को पाला पड़ा हुआ है और कागजी खेतों पर संख्याओं और शब्दों की फसल काटने का खेल, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री, गृह मंत्री कृषि मंत्री की चांडाल चौकड़ी खेलकर जनता को भ्रमित कर रही है। जब राष्ट्र की न्यायपालिका ने जनाक्रोश को देखते टिप्पणीयां करना शुरू कर दी; तो इन नयनसुखों ने न्यायपालिका के हाथ-पैर बांधने की तैयारी कर दी ताकि इन चांडालों के विरुद्ध कोई आवाज न उठाये और ये जन धन को पीस कर अपने इंडियन एब्युसिंग सर्विस के श्वानों को खाने के लिए छोड़ दें और जनता भूखी मरती रहे।

जब जनता भूखी मरेगी, प्यासी मरेगी आतंकवाद अराजकता, असमानता, जीवन की अन्रू परेशानियों से जूझेगी, उलझेगी तो कब तक सहेगी, एक न एक दिन उठेगी और क्रांति करेगी।

वसूली, लूट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, शोषण, कब तक, कहां तक जायेगा, जबकि सब जानते हैं खाली हाथ आया था, हाथ पसारे जायेगा, इसके विपरीत लोकतंत्र में जिसे जनता के बीच से निकालकर मंच पर क्या बैठाया वोट देकर सत्ता में क्या पहुंचाया, सत्ता के मद में अंधा होकर जनहितों को पीसकर स्वयं खाने लगा और सरकार में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों को खिलाने लगा। जब खाते नहीं बना तो स्विस बैंक ले जाने लगा, दूसरी ओर जनता के मन में आक्रोश पनपाने लगा, वही आक्रोश ज्वालामुखी के रूप में फूटने और धधकने लगा है।

सत्ताधीशों में चाहे अमेरिकी, सत्ता हो, टयुनीशिया की सत्ता, मिस्र की सत्ता ओ या भारत की सत्ता में बैठे मद में चूर शासकों को अंधे बनकर शासन को चलाने और श्वानों को खिलाने का परिणाम भोगने का समय आ गया है। जागो नहीं तो हुस्नी मुबारक की तरह देश छोड़कर भागो।

बढ़ती किसानों की आत्महत्याएं- कहां जा रहा 15-16 अरब से ज्यादा

भ्रष्टाचार है, हर कदम, कृषि और जिलाधीश कार्यालयों में

पूरे प्रदेश और देश और विश्व में 2010 का मौसम भारी उच्चाणचनों से घिरा रहा, निःसंदेह यह सब बढ़ती वैश्विक उष्णता और मानव जनित उत्सर्जित प्रदूषण के परिणाम स्वरूप प्रकृति का प्राकृतिक संतुलन ही अंश था, प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिये ही प्रकृति ने इस वर्ष भीषण ठंड का वज्रपात किया था। इसके फलस्वरूप पूरे उत्तरी और मध्यभारत में ठंड शून्य डिग्री और उसके निकट तक दिस. 10 और जन. 11 में बना रहा। जिसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पूरे मध्यभारत और उत्तरी भारत के किसानों ने भोगा।

भारत में कृषि, प्रगैतिहासिक काल से ही मौसम का ही जुआ बनी रही है। तब से वर्तमान तक कृषि जुआ रही है, जिसे मौसम के उच्चावचनों को स्वीकारना होता है, स्वाभाविक है कभी लाभ होता है और कभी लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है।

म.प्र. के बड़बोले मुख्यमंत्री ने हर जगह ग्रामीणों के बीच खड़े होकर कृषि को लाभ का धंधा बनाने की न केवल बड़ी घोषणायें की थी, वरन सरकारी खर्च पर करोड़ों रु. मीडिया माफियाओं को बांटकर विज्ञापन भी छपवाये थे, बेशक इसके पीछे का एक राज यह भी था कि ये घोषणावीर कृषि को लाभ का धंधा बना पाये या न बना पाये इसके विपरीत कृषि भूमि पर जो कि नगरीय क्षेत्रों के निकट है व जिनका औद्योगीकरण या अन्य कारणों से अधिग्रहण संभावित है। उन किसानों की जमीनें खरीदकर उन्हें तात्कालिक लाभ दिलाकर जीवन भर के लिये मजदूर जरूर बना रहे है और बनाते रहेंगे। इसके लिये जब से सत्ता में आई है, कृषि भूमि की खरीद बिक्री को कानूनी तौर पर मूल बनाने, कॉलोनी माफियाओं, उद्योगों की, पूंजीपतियों की धन की गुलाम बन सारे कानून बदल चुकी है अन्य कोई भी, कहीं भी कृषि भूमि खरीदकर कालोनी काटने के लिए स्वतंत्र है। 75 एकड़ से 600 एकड़ जमीन खरीदकर कहीं भी कृषि भूमि खरीदकर

नकली खाद, बीज, कीटनाशक फिर पाले की मार, फिर सर्वे में भी भ्रष्टाचार

कालोनीइजरों को कालोनी काटने की छूट मंत्रिमंडल ने इसीलिये दी और इसलिए कृषि भूमि कानूनों को बदल डाला, इस प्रकार शिव के राज में किसानों की कृषि भूमि लाभ का धंधा बनाई जा रही है।

इसके विपरीत म.प्र. के कृषि विभाग की बात करें तो यहां बैठे संचालक से लेकर 50 जिलों के उपसंचालकों, जो हर वर्ष 5 से 7 करोड़ रु. विभाग की योजनाओं से, कृषि सामग्री विक्रेताओं, उत्पादकों, पेकर्स के लायसेंस देने पुर्ननवीनीकरण करने, अनापत्ति प्रकाण पत्र देने, स्वीकृति देने, अनुदान देने में हजम कर जाते हैं। स्वाभाविक है, जब बीज, खाद, कृषि कीटनाशक रु. 15,000 से 25,000 तक लायसेंस लेने के लिये बांटेगे, तो कैसा नकली, अस्तरीय माल कृषकों को बेचेंगे। इसका अंदाजा पाठकगण लगा ही सकते हैं। फसल का क्या हाल होगा, वह भी किसानों की आत्महत्या सिद्ध कर ही देती है।

जहां तक कीटनाशकों का हाल है, उसके संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार अकेले इंदौर में ही 16 कीटनाशक उत्पादक थे, जिसमें से 3 में ताले डल गये। 13 उत्पादक कम पेकर्स अभी भी कार्यरत है। जिनमें से अधिकांश के पास न तो इसके योग्य जमीन थी, न ही प्रयोगशाला, न डाक्टर्स, न कीटविज्ञानी, न रसायनज्ञ, न कर्मचारियों के आवास और न ही ढंग की फैक्ट्री, जो ये भी अध्ययन करके निष्कर्ष निकाल सके कि कीटनाशक का कितना असर उन कृषि कीटों पर होगा, जो वो बाजार में किसानों को बेचेंगे, उसका पर्यावरण और मानव जीवन पर कितना दुष्प्रभाव होगा, इसके विपरीत सबको धन हजम कर स्वीकृति देकर संचालक कृषि से लायसेंस आवंटित हो गये, बीज के संबंध में भी यही हाल है। बीज उत्पादकों के पास भी न तो कोई साधन है, न कृषि वैज्ञानिक, पर उन्हें भी आंख मींच, मोटा धन हजम कर स्वीकृति दे दी जाती है। बाद में उपसंचालक उनको कागजी खानापूर्ति कर अनुदान में से आधा कर उन्हें बांट देते हैं और आधा स्वयं हजम कर जाते हैं। उ.सं. इंदौर के चौरे, उज्जैन का ऊंटवाला, देवास का अग्रवाल के साथ प्रदेश भर के उपसंचालकों का यही हाल है। उसके बाद बीज उत्पादकों को बीज प्रमाणीकरण संस्था से जो प्रमाणीकरण लेना होता है, वो और भी बड़े डकैत हैं, ये सब भी कागजी खेतों पर औपचारिक शब्दावली की फसल काट, मोटी वसूली कर खुले में टेग वितरण कर बीजों को प्रमाणित कर माल बिकवाकर किसानों की बर्बादी का कारण बनते हैं।

बेशक कृषि शासकीय आवंटन से लेकर ऐसी अवैध वसूली का पैसा कृषि मंत्री, सचिव और संचालक से होता हुआ प्रधान सचिव तक पहुंचता है। यही कारण है कि दिस. 10, जनवरी और फरवरी 11 में किसान शीतलहर से गिरे पाले से बर्बाद फसलों पर आत्महत्या कर रहे थे, तब कृषि मंत्री उसे पापों का फल बताकर अपने पैसे हजम करने के कुकृत्यों पर परदा डालकर बचाने का प्रयास कर रहे थे, दूसरी ओर शासन ने किसानों की नष्ट हुई फसलों के आकंलन के लिये प्रदेश के जिलाधीशों को निर्देश दिये तो स्वाभाविक था।

उन्होंने अपने उपजिलाधीशों और सहायक व अति जिलाधीशों को कार्य सौंपा, उन्होंने हल्के के पटवारियों को सौंप दिया और पटवारियों ने भी घर बैठकर जिससे आधे मिलने की संभावना थी उनको सबाको पात्र माना, चाहे उस किसान ने फसल बोई हो या नहीं, चने की फसल में सरसों और सरसों की फसल में गेहूं की फसल दिखाकर मुआवजा बंटवा दिया। स्वाभाविक था इसमें भी एडीएम एसडीएम और जिलाधीश का हिस्सा होने के साथ-साथ कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री का भी हिस्सा था; जैसा कि हर मुआवजा या क्षतिपूर्ति वितरण में हमारे देश की भ्रष्टाचार की परंपराओं में होता आया है।

जब हमारे मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर असफल होते नजर आये तो उन्होंने केंद्र के खिलाफ क्षतिपूर्ति न देने का आरोप लगाकर उपवास की नौटंकी की, उसे भी देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज भोलु सरदार ने आश्वासन की खुट्टी पिलाकर, उपवास के रंगमंच पर प्रारंभ होने से पहले ही स्वंय मुख्यमंत्री ने नौटंकी का पटाक्षेप कर दिया; सौदेबाजी किसानों के सीने पर और मृत किसानों की लाशों पर कर धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होते ही समाप्त हो गई। इस आवंटन का अनुपात 30:30:40 का होगा, 30% मुख्यमंत्री सीधे, 30% कर्मचारी और मुश्किल से 40% किसानों को ही पहुंच पायेगा।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने किसान संघ ने जब राजधानी की सड़कें जाम कर दी थी, जो मिस्र में हुये सत्ता परिवर्तन के आंदोलन का ही रूप था या सबसे पहली भारत से शुरुआत थी; किसानों की 183 मांग पत्र में से 51 मांगे पूरी करने का आश्वासन देकर विदा किया था। लगभग डेढ़ माह गुजर जाने के बाद भी किसी पर भी अमल नहीं किया; जबकि आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, पंजाब की तरह यहां पर भी 33 किसानों ने पाले से बर्बाद हुई फसलों और साहूकारों के कर्ज के कारण 33 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और पिछले दस वर्षों में 15000 से ज्यादा किसानों के बारे में स्वयं मुत्रयमंत्री और उनके मंत्री मंडल ने पिछले सत्र में स्वीकार कर लिया था के बाद में भी केंद्र और राज्य के अरबों रुपए हर वर्ष बर्बाद होते रहे हैं, आखिर पैसा कहां जा रहा है, ढीले शिव के राज में अपने शासन में बैठे गणों पर लगाम लगाने की तो दूर जांच पड़ताल भी नहीं की; यहां भी सूरदास पीसें, श्वान हजम करें चल रहा है।

वैश्विक उष्णता के बढ़ते स्तर पर प्राकृतिक संतुलन का परिणाम

विश्व स्तर पर तीखी गर्मी-तीखी ठंड

वनों का विनाश, प्रदूषण का बढ़ता स्तर, वक्त है संभलो मानव

विश्व स्तर पर मार्च से अक्टूबर 2010 में तीव्र गर्मी और चुमने वाली तीखी कड़क धूप, जो विशुद्धतः घटते प्राकृतिक वनों और अरबों टन प्रतिदिन होने वाले कार्बन के यौगिकों जिसमें कार्बन डाई आक्साइट, कार्बन मोनोक्साइड से लेकर फ्लुरों कार्बन जो पेट्रो पदार्थों के जलने और उद्योगों के उत्सर्जन से उत्पन्न होकर पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में फैलती है। स्वाभाविक है। संघनित ओजोन को तरल बना देती है। ओजोन की तरलता के कारण सूर्य की किरणें सीधी तीखी धरती पर पड़ती है। जिससे तीव्रता की गर्मी पड़ी और तीव्रता की गर्मी को संतुलित करने के लिए, प्रकृति ने शीतलता का प्रभाव भी तीव्रता की गर्मी के साथ दिखाया इसका आतंक पूरी पृथ्वी पर तत्काल देखा जा सकता है।

इस मानव की लालची प्रकृति ने वनों को उजाड़ा आत्यधिक औद्योगिक प्रदूषण ने जल, भूमि और वायु के स्तर को उसकी स्वच्छता को बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही प्रकृति के चक्र बिगाड़ने के परिणाम स्वरुप इसके परिणामों को अब भोगना उसकी मजबूरी बन चुकी है। ये सब बिल्कुल वैसा ही रहा है, जैसे कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदाकर देती है। वैसे ही चंद लालची लोगों ने पूरी दुनिया को वायुमंडल और उसके चक्र को नष्ट कर दिया। परंतु परिणाम उन निरीह मानवों के साथ जिनका इन सबसे कुछ लेना-देना नहीं है, फिर भी इन सबको भोगने को मजबूर है। तत्काल में मप्र के कई जिलों में पड़ी भीषण सर्दी से पड़े पाले और तुषारापाल ने कई किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। बदलें में सीहोर जिलाधीश और एस पी उसे पागल सिद्ध करने पर तुले हुए। पाले से उज्जैन जिले में भी फसल की बर्बादी पर किसान

को दिल का दौरा पड़नेसे मौत हो गई। दमोह जिले में भी किसानों ने कीट नाशक पीकर कर्ज चुकाने के फर्ज में असफलता के कारण आत्महत्या कर ली पिछले 10 वर्षों मे लगभग 20,000 से ज्यादा किसान फसल बिगड़ने और कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर चुके है। ये है वो निरीह जनता के महत्वपूर्ण अंग जो जनता कि भूख के लिए लड़ते है और मौसम के बिगड़ते चूक से बिगड़ी फसलों के चक्कर में मृत्यु वरण करते आ रहे है।

इनके आधारभूत कारणों पर न केवल प्रदेश की वरन देश की और दुनिया के देशों की सरकारों ने शिकार, कमीशन, और वसूली की ताक में बगुलों की भांति आंख मींचकर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे है। उन्हें बस येन केन प्रकरण कमीशन चाहिए इसके लिए देश की सत्ताए, उनके प्रदूषण फैलाओं मंडल, आवास व पर्यावरण मंत्रालय, विधि मंत्रालय तक केवल खाना पूर्ति कर, तत्कालिन वाहवाही लूट कर सभी प्रदूषण बिगाड़ने वाले उद्योगोंयथा रसायन उद्योग शराब, टेवसटाइल, औषधि फैक्ट्रियों, आटोमाबाइल गैरेज से लेकर पूरा मशीनरी उद्योग, जल और वायु प्रदूषण फैला कर पूरा प्राकृतिक वातावरण बर्बाद कर रहा है। इसके साथ कृषि में बढ़ते रासायनिक खादों के साथ कीअनाशकों के प्रयोग से न के प्राकृतिक चक्र बर्बाद हो रहा है, वरन कृषि मित्र समझे जाने वाले से कड़ी जीवॉ जिसमें सांपों, केंचुओं, मेंढ़कों, उल्लुओं, कीट सैकड़ों प्रजाति की चिड़ियों और पक्षियों की प्रजातियां जिसमें चील, कौंओं, गिद्धों की प्रजातियां भी शामिल है या तो नष्ट हो चुकी है या नष्ट होने के कगार पर आ चुकी है। पर इन सबसे बेपरवाह होकर कृषि विभाग, उद्यानिकी, वन विभाग प्रदूषण मंडल केवल कमीशन खोरी में जुटे रहकर इन सबको रोकने और प्रतिबंधित करने की अपेक्षा उल्टे ही इन सबको कागजी खाना पूर्तियां करके बढ़ावा ही दे रहे है। जिसकी घातकता का परिणाम सामने है। वायुमंउल में शीघ्रता से संघनित ओषजन का स्तर अत्यधिक तरल हो जाने से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आत्यधिक तीव्रता और तीखापन लिए होती है।

जिससे एक तरफ पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पृथ्वी पर तीव्रता से जल अवशोषित होता है। और नमी के अभाव से पेड़ पौधे और वनस्पतियां नष्ट होने से इन पर आश्रित सहस्त्रों किस्म के जलचर, थलचर और नम जीवों का हास भी हो रहा है। प्रतिदिन पर्यावरण की इस दोहरीमार से 250 किस्म की जानवरों और वनस्पतियों की प्रजातियां नष्ट हो रही है, ये तथ्य स्वयं वन विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किए है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

म.प्र. रोड डकैत कार्पोरेशन- लूट की पूरी छूट

अधिकांश सड़कों पर थिगड़े- 3 वर्षीय पुर्ननवीनीकरण कैसा?

महीना वसूली कर डकैत सचिव चुप
अधिकांश सड़कें बर्बाद

वसूली हर वर्ष बढ़ी हुई दरों पर

म.प्र. में सड़क विकास के नाम पर म.प्र. सरकार उसका धूर्त शिव मु.मु., लोक निर्माण मंत्री नागोद, प्रधान सचिव के.के. सिंग, और सचिव सह प्रबंध संचालक, जिसमें शिव अध्यक्ष नागोद उपाध्यक्ष, म.प्र. शासन मुख्य सचिव और उपाध्यक्ष म.प्र. सड़क रोड डकैत कार्पोरेशन है। पूरे सड़क डकैती निगम में बाकी सारा स्टाफ मुख्य अभियंता से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों में या तो सवो निवृत्त हो चुका है, या सभी कार्य विभागों यथा, म.प्र. लोक निर्माण, म.प्र. जलसंसाधन, म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय से लेकर, ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग से प्रतिनियुक्ति पर बुलाया हुआ है। स्वाभाविक है, अगर सड़क डकैती निगम में कानून से काम करवाने की बात करते हैं तो अध्यक्ष शिव, उपाध्यक्ष व लो.नि.वि. नागोद, म.प्र. शासन मुख्य सचिव और उपाध्यक्ष अवनि वैश्य और लो.नि0वि. सचिव और प्रबंध संचालक विवेक अग्रवाल को हर महीने करोड़ों रुपए की लूट की हिस्सेदारी ठेकेदार पूरे म.प्र. की सड़कों पर वसूल कर क्यों देगा?

म.प्र. रोड डकैते कार्पोरेशन के अंतर्गत चल रही पूरे प्रदेश की सड़कों पर हर वर्ष 7% से 48% की वृद्धि तो की जा रही है; पर वास्तविकता में इसे अंतर्गत आने वाली सड़कों की हालत भारी दयनीय है, जो म.प्र. लोकनिर्माण विभाग द्वारा रखरखाव की जारी रही। सड़कों से भी बदतर है। उज्जैन आगर झालाबाड़ सड़क पर ही ले लो यहां के ठेकेदार ने एकहरी सड़क पर तीन वर्ष में पुर्ननवीनीकरण की तो दूर पेंचवर्क कर गढ्डे भी ढंग से नहीं भरे; यही हाल रायसेन से राहतगढ़ सड़क मार्ग का भी है। यह एकहरी 12 फुट सड़क है, जिस पर .....के ठेका हरामखोरों सविनि में बैठे धूर्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, व डकैत निगम का संचालक पूर्व में सुलेमान और अब विवेक अग्रवाल यहां तक नहीं देख रहे कि इस सड़क पर दोनों तरफ 5 फुट की कच्ची मुरम से भरी ठोस पट्टी ....नहीं बनाई, हाल इस सड़के के इतने बदतर हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन के चौमार्गी (फोर लेन) से कम पर टोल नहीं लगाया जायेगा के विपरीत इन डकैतों ने बनी बनाई सड़कों पर करोड़ों रुपए प्रति किमी. के न केवल इस्टीमेट स्वीकृत किये वरन उन पर अनुदान भी अपने कमीशन डकारने के लिए मुक हस्त से बांटा गया; जबकि बीओटी के खान ठेकेदारों जिसमें एमएसकेके पास खंडवा, होशंगाबाद जैसे अनेकों सिंगल लेन रोड भी है। इस 185.6 किमी. सड़क पर 3 वर्ष के बाद न तो सड़क मार्ग संकेतक लगे हैं न अब पेंच वर्क किये जा रहे हैं पुर्ननवीनीकरण की तो सोचना भी निरर्थक है। यह भ सिंगल रोड है इस पर भी रखरखाव शून्य है पर वसूली हर वर्ष बढ़ा कर की जा रही है; जबलपुर नरसिंगपुर, पिपरिया 141.27 किमी. जो जेएनपी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जलगांव नाम के खान के हाथ में है। इसे भी रुपए 45.81 करोड़ का अनुदान दिया गया, सड़क पर न तो मार्ग संकेतक हैं। रखरखाव इसका भी घटिया होने के साथ पुर्ननवीनीकरण का भी सारा पैसा हजम हो रहा है। होशंगाबाद मार्ग होने के साथ ही ये हरामखोर चेतक इंटरप्राइजेस न तो सुरक्षा के इंतजाम किये हैं।

न ही दोनों तरफ की पट्टियां भरी गई हैं। जबकि इस खान को दिये गये अनुदान रुपए 59.88 करोड़ में से भी आधे डकार कर सड़क पर एक परत बारीक चूरी की रुपए 25 लाख किमी. में बिछा दी गई थी। देवास, उज्जैन, बड़नगर, बदनावर 98.29 किमी. यह भी सिंगल लेन सड़क है, यह खान आर.व्ही, इंजीनियर प्रा.लि. बेंगलोर को रुपए 24.27 करोड़ अनुदान के साथ दी गई इसने भी रुपए 25 लाख किमी. खर्च कर सरकारी पैसे से ही काम कर वसूली शुरू कर दी। अधिकांश सड़क डकैत निगम ने जो अनुदान दिया ठेकेदारों को उन हरामखोरों ने प्रति किमी. सड़कों पर, निगम डकैतों उसी .....डकार कर ठेकेदार डकैतों को बिना काम पूरा किये,सड़कों पर यहां तक कि मार्ग संकेतकों तक के अते-पते नहीं है, जिसमें प्रदेश का सबसे पुरानी बीओटी सड़क इंदौर इदिलाबाद पर भी 7 वर्ष की वसूली के बाद भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से न तो पूरे संकेतक लगाये हैं। न ही पुर्ननवीनीकरण किया जाता है। न ही पूरे मार्ग की पट्टियां भरी गई हैं। न ही घुमावों, सड़क से लगे ढलानों पर जबकि सड़कों से लगी ढलान 5 फुट से लेकर 100 फुट तक होने के बाद भी वैरीकेटस का भी पता नहीं है। इसे भी 203 किमी. सड़क पर रुपए 50 करोड़ का अनुदान दियाग या था।

यह 2 लेन रोड है। प्रदेश की 33वीं ओटी सड़कों के 60 टोल बूथों पर वसूली तो हर वर्ष बढ़ाकर की जा रही है पर ये शूकर सचिव सह प्र.सं. विवेक अग्रवाल जो अपने आप को म.प्र. भारत ही नहीं दुनिया का भी श्रेष्ठ बुद्धिमान समझता है। महाडकैत अपना धन डकारने और उस पर किसी की निगाह नहीं जाए चारों तरफ प्रतिनियुक्तियां सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य अभियंता से लेकर 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को बहुत ही बत्तमीजपूर्ण तरीके से डांटता-फटकारता है। इसके विपरीत प्रदेश के 33बीओटी ठेकेदार जो सड़कों पर वसूली कर इन 4 श्वानों मु.मं. मु.स., लोनिवि मंत्री नागोद, चौथा चांडल अग्रवाल को टुकड़ा डालते हैं। नियम कानूनों के अनुसार सड़कों की गुणवत्ता और सभी टोल बूथों पर एंबुलेंस, क्रेन चालकों के लिए स्नानागार, शौचालय आदि की 7, 5, 3 2 वर्षों बाद भ नहीं करवा पाये, उनसे भी सड़कों के स्तर और रखरखाव की बात नहीं करता, बस महीना समय पर चारों चांडालों को पहुंच रहा है या नहीं यह देखता है।

रायसेन-राहतगढ़ के पूरे मार्ग पर 5-5 फुट की दोनों तरफ पट्टियां तो कहीं बनाई ही नहीं गई; मार्ग संकेतक भी नहीं, सिंगल लेन रोड में घाट सेक्शन में तो कई स्थानों पर 100-200 मी. तक सड़क का ही नामोनिशान नहीं। सड़कों को घनी आबादी से गुजारा जा रहा है, कहीं बाईपास भी नहीं; रीवा टोल वे प्रा. लि. की सतना मैहर उमरिया 129.27 किमी., रीवा जयसिंगपुरा शहडोल-अमरकंटक मार्ग 242.70 किमी. इन हरामखोरों ने भी जो प्रारंभ में मोटरेबल सड़क पर जो डामर की एक परत का पोता मारा था वही चल रहा है। उसके बाद इन हरामखोरों ने भी कोई काम पूरा नहीं किया न ही गड्ढे भरे और न ही पुर्ननवीनीकरण किया।

भोपाल देवास कारीडोर में भी अनेकों स्थानों पर सड़क 5'-5' चौड़ी नहीं की जाकर पट्टियां नहीं भरी गई; साथ ही अनेकों किमी. में सड़क तल से 2' की चौड़ाई के बाद ही 3-4 फीट के गड्ढों पर भी बेरीकेटस नहीं लगाए गये। मील के पत्थर भी नहीं टोल नाकों पर क्रेन, एंबुलेंस के भी पते नहीं हैं। यही हाल इंदौर-उज्जैन का भी हैं पूरे 33 मार्गों पर लगभग 3000 किमी. सड़कों को बनाया गया जिसमें करीब रुपए 1500 करोड़ की रायल्टी भी इस रोड डकैत कार्पोरेशन के साथ मिलकर ठेकेदारों ने हजम कर ली। जिस मुख्य सचिव अवनि वैश्य को ईमानदार मुख्य सचिव कहा जाता है न्यूनतम रुपए 500 करोड़ प्रतिमाह पूरे प्रदेश के सभी विभागों से आवंटन में से प्रदेश की संपत्तियों की नीलामी, जिसमें म.प्र. विद्युत मंडल, सड़क परिवहन निगम, कृषि भूमि बेचने आदि से कमाई हो रही है। धड़ल्ले से सारे कानून बदले जा रहे हैं। कानूनों को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

'राज' तंत्र से लोकतंत्र ज्यादा भ्रष्ट और निकृष्ट

मिस्र में 18 दिन के लंबे आंदोलन के बाद आखिर हुस्नी मुबारक ने 30 वर्ष पुरानी सत्ता त्याग ही दी, वहां राजतंत्र का अंत हो गया। इसके पूर्व टयुनी शिया में भी ऐसी ही क्रांति हई थी और टयुनीशिया में भी राजतंत्र का अंत हो गया; अभी यमन में भी ऐसी ही क्रांति अंगड़ाई ले रही; बहरीन में सेना ने दमन चक्र चला रखा है; मुख्य बाजारों में भीड़ पर सेना के टैंक चौकसी के लिए बाहर आ गये हैं। यही हाल लीबिया और अन्य अरब देशों में भी हो रहा है।

यहां यक्ष प्रश्न यह है कि क्या सचमुच लोकतंत्र, राजतंत्र से अच्छा होता है, क्या यहां शोषण, भ्रष्टाचार, अपराध नहीं होते, यहां पर लोक द्वारा चुना गया तंत्र, राज तंत्र से ज्यादा भ्रष्ट, निकृष्ट, निकंमा, डकैत होता है; चारों तरफ विश्व के सभी लोकतंत्रों में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जा सकता हैं

सत्ता सुंदरी वह वैश्या है, जो इसके आगोश में गया या जिसने इसका वरण किया उसे चरित्रहीन, झूठा, मक्कार और चालाक होना ही पड़ता है। अगर नहीं होगा तो भी जनता जीने नही देगी। फिर राजतंत्र में एक राजा होता है, उसकी सत्ता के आधीन सत्ता चलाई जाती है। इसके विपरीत लोकतंत्र में हर शासक जानता है कि उसकी सत्ता अगले चुनाव होने तक ही है; इसके बाद वह भी सड़क पर होगा। इसलिए सत्ता में रहते हुए जितना लूटा जा सके, उतना लूट लो, वरना सत्ता जाते ही कोई नहीं पूछता; इसलिए लोकतंत्र में राज्यतंत्र से ज्यादा भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, शोषण, अपराध और राष्ट्रद्रोहवाद पाया जाता है। विश्व के किसी भी लोकतंत्र में देखिये फिर विश्व में निगाह उठाने की जरूरत ही हनीं हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रणाली को ही देखें जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो देश की सत्ता चलाते हैं। भ्रष्टाचार, लूटखसोट, दलाली खाते हैं। मामले सामने आने पर प्रेस के सामने खड़े होकर अपनी लाचारी बताते हैं।

राष्ट्र और जनता की बर्बादी पर कमीशन खाकर इठलाते हैं। अपनी कमीशनखोरी और दलाली के लिए पहले निर्यात करवाते हैं। महंगाई बढ़ाते हैं। जब जनता चिल्लाती है; तो सड़ा-गला, स्तरहीन माल दुगुने, चौगुने से लेकर चालीस गुना महंगा आयात करवाकर उसमें भी कमीशन डकार जाते हैं। लोकतंत्र में शासक वर्तमान ही नहीं जनता की पीढ़ियों का भविष्य भी कमीशन डकार कर दांव पर लगाते हैं। अपना भविष्य सुधारने के लिए जनता का भविष्य बिगाड़ जाते हैं। जबकि राजतंत्र में गिने-चुने ही शासक होते हैं, जिन्हें अपना वर्तमान और भविष्य सुधारने की चिंता अवश्य होती है, ताकि जनता भी खुश रह सके।

लोकतांत्रिक सरकारें न केवल ज्यादा अस्थिर, बिकाऊ पूंजीपतियों की रखैल, तो होती ही है। साथ ही ये जनप्रतिनिधि घारलालची, स्वार्थी होने के कारण राष्ट्र के शत्रुओं के मोहरा बनकर अपने ही राष्ट्र के भविष्य को बर्बाद करने से नहीं चूकते। यही कारण है कि अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारों को अमेरिका जैसे राष्ट्र आसानी से सहायता के बहाने, विकास के नाम पर चंद कागज के टुगड़ों रूपी डालर बांटकर अपना मोहरा बना कर उपयोग करते हैं। जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का वर्तमान ही देखें तो यही कुछ हो रहा है वर्तमान में; जैसा कि नेपाल में हो रहा है।

यहां ईमानदार वह है, जिसे मौका नहीं मिला; फिर लोकतंत्र में तो हर चुनाव के बाद जीते प्रतिनिधियों को जैसे ही सत्ता का सुख मिलता है; सत्ता सुंदरी वैश्या के आगोश में जाते ही, सभी महाभ्रष्ट, चरित्रहीन, बेईमान मक्कार, निर्लज्ज हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे राष्ट्र में सरपंच पंचों से लेकर, पार्षद, विधायक, सांसदों के बारे में देख सकते हैं। देख रहे हैं। जो सत्ता में रहते हैं। वो लूटते हैं। उनहें मालूम रहता है, कि अगले चुनाव तक जो लूट सके, लूट लें, जैसे भी हो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर, सरकारी संपत्तियां बेंचकर, सरकारी जन, धन में सेंध लगाकर, जनता का शोषण करके, अगले चुनाव में तेरा न जाने क्या हो कालिया टिकिट मिले न मिले, जीते न जीते, जीत भी जाएं, सरकार तेरी पार्टी की बने न बने। सत्ता सुंदरी राजतंत्र की होगी तो कम से कम राजा ही दुरुपयोग करेगा; पर लोकतंत्र में, हर चुनाव केबाद नये नंगे-भूखों की फौज आते ही फिर नोंच खसोट में लग जाती है। उसके नोंच खसोट और वसूली के तौर तरीके ही अलग होते हैं। जिसको भी सत्ता में जनता बैठाती है। मानवीय स्वभाव के अनुकूल सभी काम, क्रोध, मद, मोह, माया की पूजा में लीन हो जाते हैं, जिसके घिनौने रूप आये दिन जनता देख रही है।

99% आईएएस, आईपीएस, आईएफएस भ्रष्ट

प्रथम पृष्ठ का शेष

जैसे गंभीर अपराधों में बढ़ोतरी ही हुई है। जितना बड़ा अधिकार उतनी मोटी वसूल भी चाहिए। और वसूली तब ही से ज्यादा होगी जब ज्यादा अपराध होंगे। फिर मप्र के गृह विभाग में कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों, सहा.निरीक्षकों उप निरीक्षकों की भले ही कमी हो, भर्ती वर्षों न भी हो परंतु आईपीएस तो संघ लोकसेवा आयोग से चयनित किए जाकर थोप ही दिए जाते है। चाहे फिर उनके लिए नए पद ही क्यों न सृजित करना पड़े।

आईएफएस अर्थात इंडियन फोरस्ट ईटिंग सर्विस

जैसे-जैसे दवा देते गए- दर्द बढ़ता गया। यह कहावत तो पूरे प्रशासन पर लागू होती है। कि जैसे अधिकारी बढ़ते गए, भ्रष्टाचार बढ़ता गया। जैसे पूरे प्रदेश के और देश के राज्यों के वन विभागों में आईएफएस बढ़ते गए। जंगल कटता और घटता गया। 95प्रतिशत आईएफएस अधिकारियों को वेतन केक अतिरिक्त अगर रु. 10-20 लाख प्रतिमाह न मिले तो किस बात की फारेस्ट ईटिंग सर्विस, अब रु. 10-20 लाख कमाने के लिए बेशक पूरा शासकीय आबंटन तो नहीं उकारा जा सकता। फिर क्षेत्र में बैठे रेंजर के माध्यम से खर्चों के फर्जी व्हाउचर लगाए जाते है। तो 25प्रतिशत उसे भी चाहिए। तो भी 50 प्रतिशत कुल आबंटन में ज्यादा नहीं उकार सकते। अब बचती है, तो वन भूमिकी अपार संपत्ति एक तरफ जंगल से पेड़ कटवाओं और बेंचो दूसरी तरफ रु. लाख, दो लाख रु. एकड़ में जमीने ग्रामीणों को दे दो, बाद में पट्टे दिलवा दो। उससे भी फसल आने पर प्रति एकड़ कमाई का 25 प्रतिशत हिस्सा किसान से वसूल लो। फिर वनों से अवैध खनिज, गिट्टी, मुरम आदि बिकवाते रहो। वनोंपजों की चोरी करवा कर बिकवा दो। जंगल में वन प्राणियों के शिकार करवा कर उनकी खालें बिकवाते रहो। पुलिस वालों की तरह अपराधियों को चढ़ाओं बढ़ाओं और पकड़ों तो भी खुलकर वसूली करो।

अधिकांश आईएफएस इस प्रकार से अरब पति हो जाते है। रेंजर जो फिल्ड में है करोड़ों की संपत्तियों के मालिक होते है तो फिर आईएफएस को तो शान बचाए आर बनाए रखने के लिए अरब पति होना ही चाहिए। आखिर लोकायुक्त वाले सब जानकर भी चुप रहते हैं। ने भी कुछ नहीं किया अब यह स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव है। स्वास्थ्य विभाग अपनी दवाओं की, औषधि और चिकित्सालयों की खरीदी में 25 से 80-90प्रतिशत और कई प्रकरणों में 100प्रतिशत तक धन उकारने का आदि रहा है। फिर सुधि रंजन किस बात का राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्तकर लाए। जिस स्वास्थ्य विभाग में हर कदम लूट, वसूली और भ्रष्टाचार का बोलाबाला हो। उपर से भ्रष्ट अधिकारियों को बैठाया जाना क्या सिद्ध करता है। सब मिल बांट कर खाओं। इन सारे अधिकारियों का पैसा भारत के अतिरिक्त स्विस बैंकों के साथ, कुकुरमुत्तों की तरह चल रहे फार्मेसी, इंजिनियरिंग, प्रबंधन आदि के कालेजों में भी लगा है। साथ ही प्रदेश में आए राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय कालोनाइजर्स को भी इन्हीं का धन और संरक्षण मिला हुआ है। मप्र के अनेकों उद्योगों के साथ देश के आने के उद्योगों में भी धन विनियोजित है।

मप्र की सरकार केक मुखिया शिवराजसिंह को भी भ्रष्टों और हरामखोरों से विशेष लगाव है। जिसका छोटा सा उदाहरण है, सचिव अनुराग जैन जिसने जैन समाज के नाम मेडिकल कालेज खोलने के लिए रु. 1प्रति वर्ग फूट की जमीन हथियाई फिर इस भ्रष्ट ने धीरे-धीरे जैन समाज को अलग कर पूरे कालेज को अपने नाम से करने का षड़यंत्र रचा। दुसरी और यह सूचना प्राद्योगिकी का सचिव है। इसने हाल ही में डाटा बैंक का ब्लेका किसी अंतराष्ट्रीय स्तर की भारतीय कं. को देने के लिए 70 से 30 प्रतिशत का प्रस्ताव रखा तो कंपनी के अधिकारी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। तो इसने उस कं. को 6 माह के लिए ब्लेक लिस्टेड किया अब यह रु. 250 करोड़ में से रु.200 करोड़ से ज्यादा हजम करने के लिए किसी कंपनी को ढूंढ रहा है। जो डाटा बैंक के नाम पर ठेका भी ले ले और पेसा भी इसे दे, दे जब ऐसे भ्रष्टों को मुख्यमंत्री अपनी आस्तीन में पालता है तो प्रदेश के 90 प्रतिशत भ्रष्टों को तो संरक्षण देगा ही। ताकि उसका हिस्सा भी मिलता रहे ।

यही हाल इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस के पुलिस अधिकारियों का भी है इनकी कमाई भी फील्ड में आते ही प्रति वर्ष गुणात्मक श्रृंखला में अर्थात् 2,4,8,16 के अनुपात में बढ़ती है अधिकांश 10 वर्ष भी अगर फील्ड में गुजार लें तो अरब पति हो जाते है। इनके भ्रष्टाचार के कसीदों में सर्वोच्च न्यायालय भी हर वर्ष 25-50 बार पढ़ता है। ये भी सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की कठ-पुतली होते है। इनपर आयकर भी छापे नहीं डालता, लोकायुक्त सीबीआई, ईओ डब्ल्यू आदि में इन्हीं सब का बोलबाला होता है। सांई ट्रेवल्स की बस में 5 फर को छतरपुर से लौटते समय उसके कर्मचारियों ने बताया हमारे अरविन्द श्रीवास्तव भी आईपीएस है पूछा कितनी बसें है। तो मालूम पड़ा कि 100 से ज्यादा बसें है। जो पूरे मप्र के साथ ही नागपुर, झांसी, रायपुर के अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी चलती है। इसलिए हमें किसी से डर नहीं लगता हमारी बसें कोई नहीं छूता।

साप्ताहिक समय माया

कम्प्यूटर खरीदी में करोड़ों का कमीशन

वाणिज्य कर कदम-कदम भ्रष्टाचार

सूचना के अधिकार में जानकारी के नाम, अधिकांश जालशाज आवेदकों को करते है परेशान

इंदौर में वाणिज्य कर मुख्यालय में पिछले 4 वर्षों में कम्प्यूटराइजेशन के नाम पर किस प्रकार बंदखांट की गई उसके खरीदी के आधे अधूरे बिलों के भी बारिक विश्लेषण से बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाती है जो कि सूचना के अधिकार में मांगे गए थे। इसमें भी उन्होंने माल आपूर्ति के आदेशों की प्रतियां नहीं दी गई। करोड़ों रु. के कम्प्यूटर्स के बिल पास किए गए परंतु उसमें क्या सामान खरीदा गया। उसकी सूची भी नहीं करवाई गई फिर भी वास्तविक अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है। कि दो वर्ष पुराने अच्छे चलते हुए हाई कानफिगेशन के ब्रांडेड कं. के करोड़ों रु. के कम्प्यूटर्स को मात्र 40 प्रतिशत कमीशन उकारने के लिए कचरे में फेंक कर जिस टयूलिप कम्प्यूटर्स राइट टाउन जबलपुर से खरीदी की गई उसकी कमीशन खोरी की चालबाजियां लगातार अब प्रकाश में आने लगी है और उसकी लगातार खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है।

अगर खुले बाजार से यही कम्प्यूटर्स खरीदे जाते तो 25प्रतिशत ही कीमत खर्च होती परंतु जिस टाटा कंसलअेंसी की सहायक क्र. के रुप में काम कर टयूलिप का नाम सामने आ रहा है उसका मकड़जाल केन्द्र से लेकर देश के अनेाके राज्यों में भी टीसीएस ने इसी प्रकार कमीशन बांटकर सब जगह अपने मोटे बिल शासन के खाते से पास करवा कर मोटे-मोटे लाभ कमा रही है।

टयूलिप टेलिकॉम लि. राइट टाउन जबलपुर द्वारा जारी की गई इंवाइस ने टीटीएल/एमपी/14/08-09 मार्च, 4,2009 खरगोन में कम्प्यूटर लगाए गए जिसका बिल रु.20,19,283 का था। जिसमें 5.5 प्रतिशत डिस्काउंट काटकर 113311 बिल बनाया गया रु. 19,55,472 का बाद में बिल पास किया गया रु. 13,68,831/- रु. में खरगोन वृत्त में आठ कम्प्यूटर्स सेट भी लगाए गए। रु. 50,000/ -जिसमें प्रिन्टर्स, सीपीयु, मानीटर सभी कुछ ब्रांडेड भी था तो भी रु.4 लाख के पर रु. 20 लाख 70 हजार के बिल को काटकर रु.13.69 लाख का भुगतान कैसा और क्यों अर्थात अगर सन् 2008 में दरें निर्धारित की गई थी तो भी 400 प्रतिशत अधिक के बिल पास किए गए बंदरबांट का अंदाजा इसीसे लगाया जा सकता है। जिस काटापीटी को यहां दर्शाया गया उसका आगे टीटीएल/ मप्र/शेष 01, से 70 प्रतिशत राशि का रु. 34,25,111/- क्र.2 से 20 प्रतिशत राशि का रु. 97,19052/ -, शेष क्र3 से शेष 20प्रतिशत का रु. 1,08,94,929/- शेष क्र. 4 से 20 प्रतिशत शेष का भुगतान रु. 100,31, 298/-, शेष क्र.5 से 20 प्रतिशत शेष का भुगतान रु. 93,20,075/- शेष क्र.06 से 70 प्रतिशत व 90 प्रतिशत का भुगतान रु.34,67,810/- और अतिरिक्त बि.क्र.1, अतिरिक्त उपकरणों का 90 प्रतिशत का भुगतान रु.37,27,977/- का सभी दि. 06/1/2010 में किए गए 4,68,58,275/- वेट साथ अति.90प्रतिशत का भुगतान जोड़ने पर रु. 5,03,26,085/- का भुगतान भी कमीशन हजम करने के लिए किया गया।

कम्प्यूटर हार्डवेयर की भोपाल में आपूर्ति का बिल क्र. 23/08-09 दि.10/2/09 रु. 1,25,50,140/- का था रु. 83,01,917/- का पास किया गया। अब भोपाल में अधिकतम डीसी, एसी और वृत्तों में कुल 40 से ज्यादा कम्प्यूटर तो लगाए नहीं गए और 40 भी मान ले, तो रु.20 लाख की ही कीमत हुई। देवास में बिल क्र.27/08-09/ दि. 4/3/ 09 देवास में अधिकतम 10 कम्प्यूटर्स कीमत 5 लाख जिसमें सीपीयु, मानिटर, प्रिंटर्स के साथ में, बिल दिया गया रु. 20,25,344/- पास हुआ रु.14,74,741/- खंडवा में अधिकतम कंप्यूटर्स 16, कीमत 8 लाख बिल लगाया गया रु.31,62,234/-पास हुआ रु. 22,13,565 अर्थात रु.14 लाख अधिक जबलपुर में अधिकतम कम्प्यूटर्स 30 सेट बिल रु.77,18,401/-(-)5.50 प्रतिशत डिस्काउंट, रु. 72,93,889/- पास हुआ रु. 51,05,622/- यहां रु. 25 लाख अधिक्य का भुगतान हुआ। रतलाम साइट पर अधिकतम 22 सेट बि.क्र.13/08-09 दि.19/1/09 बिल रु.38,20,972/- पास हुआ रु.26,74,680/- रु.15 लाख का अधिक भुगतान किया गया। 25 बिल के भुगतान के संबंध में अगे समाचार पत्र में दिया जा सकेगा।

अर्थात टयूलिप टेलिकॉम लि. को 60 से 70 प्रतिशत अधिक भुगतान किया गया। जो कि टाटा कंसलटेंसी का सहयोगी संस्थान है। वैसे भी न केव टाटा की मप्र सरकार वरन् देश के सभी राज्यों की सरकारें टाटा जैसे पूंजीपति की कठपुतली है। क्योंकि वह मोटा कमीशन बांटकर मोटे ठेके हथियाता है। टाटा कंसलटेंसी केन्द्रीय सरकार से लेकर राज्यो की सरकारों में अधिकांश कम्प्यूटर्स, साफ्टवेयर्स के सभी विभागों के ठेके मोटे कमीशन बांटकर, अंधी कमाई करता है।

बेशक अब इसी वाणिज्य कर में हाईवेयर और साफ्टवेयर का यह कमीशन आयुक्त से लेकर प्रधान सचिव मंत्री, राघव जी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भी पाइप लाइन से निश्चित हिस्से के अनुसार गया ही है। यही कारण है, कि अंधों की रेवड़ी की तरह ठेके खरीद और साफ्टवेयर के हर विभाग में दिए जाते है।

वित्त मंत्री राघव जी के पास वाणिज्यकर और आबकारी जैसे मलाईदार विभाग है।जिसकी वसूली वाणिज्यकर का वर्तमान में राघव जी का विशेष पात्र एसी, एसडी रिछारिया करता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार आबकारी और वाणिज्य कर में स्थानांतरण, पदस्थापना आदि में खुलकर लेन-देन चल रहा है।

शराब माफिया के इशारे पर नाच रही शिव सरकार

अप्रैल से आबकारी के बंद हो जायेंगे बॉटलिंग प्लांट

सीधे कमीशन डकारेंगे मंत्री, सचिव शराब ठेकेदारों से

म.प्र. की भाजपा की शिवराज की सरकार शराब माफिया और पूंजीपतियों की रखैल बन प्रदेश को हांक रही है। पूंजीपतियों, कालोनाइजरों, उद्योगपतियों के लिये वह सब कुछ कर रही है और करने को तैयार है। उसके लिये नियम कानूनों में न केवल बदलाव किये गये, वरन नये कानून भी बनाये गये, वैसे भी सरकारें चाहे भाजपा या कांग्रेस की हो, सब जानते हैं कि नेताओं, मंत्रियों की औकात 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होती, इसलिए दोनों हाथों से राष्ट्र की, प्रदेश की, नगर की, गांव की, जहां भी मौका मिले उसकी संपत्तियों को मोटा कमीशन खाकर नीलाम करने, गिरवी करने बेचने पर तुले हुए हैं। म.प्र. सड़क परिवहन निगम को बंद करके, सारे राज्य के और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों के वाहनों को चलाकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में यात्रियों का शोषण किया जा रहा है, दूसरी तरफ परिवहन निगम की संपत्तियों, बस स्टेण्डों, डिपो, कार्यालयों की जमीनों और भवनों को बेच कर वारे-न्यारे किये जा रहे हैं। इसी पेटर्न पर चलकर सरकार द्वारा माफियाओं के लिये सरकारी बॉटलिंग को भी शराब माफियाओं के हवाले करने और करोड़ों के वारे-न्यारे करने की नियत से सरकारी बॉटलिंग को बंद कर रही है 1 अप्रैल 2011 से, ताकि करोड़ों रु. का कमीशन सीधे शराब माफियाओं से हर महीने ऊंची दरों पर शराब खरीदने में हजम किया जा सके, इसकी तैयारी में स्वयं आबकारी विभाग ने अपने ही बनाये नियम कानूनों को देशी मदिरा के मामले में 2009-10 में तोड़ा उसने इन डिस्प्लर्स को सरकारी नियमों और कानूनों को बलाये ताक रखकर सीधे आठ रु. तक बढ़ाया जबकि कानूनन रु. से एक वर्ष में रु. 3 प्रति प्रूफ लीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता था, परन्तु 09-10 में दस वर्षों से चले आ रहे नियमों को बलाये ताक रखकर एक साथ रु. 8 की वृद्धि कर जहां डिस्टलर्स को फायदा पहुंचाया गया वहीं रु. 4/- प्रति प्रूफ लीटर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर आबकारी आयुक्त, जिसमें आबकारी मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव आदि सभी थे रु. करोड़ों प्रति माह के वारे-न्यारे कर शासन को भी अरबों रु. की चोट पहुंचाई गई, जब शराबियों को महंगी शराब मिलेगी तो अवैध शराब का भी कारोबार बढ़ेगा।

दूसरी ओर रु. 8 प्रति लीटर की वृद्धि के पीछे शराब माफियाओं ने जो तर्क दिया कि कोयले की कीमतों में जो रु. 1672 प्रति टन था जो रु. 2991 प्रति टन हो गया जबकि इस संबंध में सबसे बड़ा तथ्य यह था कि जब डिस्टलर्स कोयले का उपयोग करते ही नहीं तो कोयले के आधार पर कीमतें बढ़ाने का बहाना न केवल निराधार है वरन स्पष्ट ढंग से केवल डिसप्लर्स को अधिक भुगतान कर शासन को चोट पहुंचाने और रु. 4 प्रति प्रूफ लीटर का कमीशन डकारने के लिए हां किया गया था, जब इस बात की मांग विभागीय मोटे कमीशनखोर अधिकारियों ने डिस्प्लर्स एसोसिएशन के माध्यम से आयुक्त अरुण पांडे पर दबाव डालकर रु. 8 प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा गया जब आयुक्त ने इससे साफ इंकार कर दिया, जब पूरी डिस्पलर्स ऐसोसिएशन को एहसास हो गया कि यह बढ़ोतरी नहीं होगी, तो बिके हुए मंत्री, सचिव, प्रधान सचिव ने मोटा कमीशन पाने के लिये आयुक्त अरुण पांडे को ही विभाग से हटा दिया गया, और बाद में आयुक्त अरुण भट्ट से कार्य करवाया गया, विभागीय सूत्रों से मिली सूचनाओं के अनुसार अब शराब लॉबी के इशारे पर शासकीय बॉटलिंग प्लांट जो देशी, प्लेन, मसाला और नारंगी देशी ठेकों पर बिक्री हेतु आपूर्ति करते हैं। पूर्ण रुप से बंद किये जाने और निजी माफियाओं को देने की तैयारी कर ली गई है। ताकि बॉटलिंग में छोटी मोटी हेरफेर से एडीओ, डीईओ को जो कमाई हो जाती है उसे सीधे ही ये डिस्प्लर्स से लेकर हजम कर सके, सरकारी बॉटलिंग में देशी, प्लेन, मसाला, दुबारा आदि की जो गुणवत्ता और मानक का पालन किया जाता था, स्वाभाविक तह स्तर तो मिलने की दूर उठे ही मोटा कमीशन डकारने के चक्कर देशी ठेकों पर आपूर्ति के लिये जो माल खरीदा जायेगा न तो उसमें उस स्तर पर स्प्रिट का वह प्रतिशत होगा, न ही गुणवत्ता का स्तर, फिर वर्ष दो वर्ष दरें स्थिर रहेंगी, बाद में डिस्टलर्स और बॉटलिंग करने वाले, कीमतों भी अधिक वसूलेंगे, इसके परिणाम स्वरूप अवैध शराब बनाने वालों को मौका मिलेगा और खुले में अवैध शराब की बिक्री बढ़ेगी जिससे शासन को राजस्व की हानि होने के साथ ही जहरीली शराब कांडों की पुनरावृत्ति बढ़ेगी, शायद सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव, प्रधान सचिव भी यही चाहते हैं कि जनता मरे तो मरे, शासन को राजस्व की भले ही हानि हो परन्तु डिस्प्लर्स, बॉटलर्स से मोटा कमीशन वेतन की भांति हर महीने ब्रीफ केसों और सूटकेसों में घर अवश्य पहुंच जायें।

यह तथ्य भी स्पष्ट है कि पूरा आबकारी विभाग जिसमें सिपाही से लेकर निरीक्षक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहा. आयुक्त, उपायुक्त, आयुक्त तक अनेकों स्त्रोतों से भारी कमाई करते हैं। अवैध शराब, शराब की दुकानों से नियम विरुद्ध कार्य करने अधिक कीमत पर शराब बिकवाने आदि में खुली छूट देकर महीना वसूली करते हैं। यही हाल गांजा, भांग आदि की दुकानों, लायसेंस होलर्स से भी किया जाता है। पूर्व में पदस्थ एडीओआर के जैन, एम.एस. बघेल आदि के पास करोड़ों की धनसंपत्ति इसी प्रकार आई, एडीओ आर.के. जैन वर्तमान में रतलाम डीईओ है और एडीओ बघेल छतरपुर में है। एडीओ आर.के. जैन ने इंदौर में दीर्घकाल तक हर स्थान पर कमाई की है, जिसके भ्रष्टाचार और लूट खसौट के किस्से समाचार पत्रों में भी कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। एडीओ बघेल के पास इंदौर में ही करोड़ों की संपत्ति है जिसमें कालिंदी कुंज का बंगला, दो लड़कियों के नाम से प्लॉट भी खरीदे गये हैं। इसकी कुछ संपत्ति भोपाल में भी है। यह हरामखोर अपने आप को राजघराने से बताकर चारों तरफ रौब ऐंठकर भी पैसा वसूली करता है। आबकारी विभाग के सूत्रों से पता चला है कि ये धन कमाने के लिये कमीशनखोरी और वसूली के लिये पारंपरिक तरीकों के अतिरिक्त पूड़िया कांड भी करता है, जिसमें किसी के पास भी नशे की पुड़ियाओं को पकड़वाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। केस को खत्म करने में लाखों रुपये की वसूली करते हैं। वैसे ये कारनामें महीने में एक दो बार बदला लेने के हिसाब से भी किये जाते हैं। अगले अंकों में पढ़िये।

सबसे बड़ा मिलावटिया रिलायंस...

प्रथम पृष्ठ का शेष

की जांच का कोई भी ठोस आधार, मिलावट सिद्ध करने के लिए न केवल म.प्र. सरकार वरन केंद्रीय शासन के पास भी नहीं, जिसे न्यायालयीन प्रक्रिया में लाकर उसे सजा दिलवायी जा सके। केंद्र शासन के पेट्रोलियम मंत्रालय के आधीन काम कर रही तीनों तेल वितरण कंपनियां स्वयं ही इस खेल में शामिल हैं, तो उकनी प्रयोगशालाएं न्यायालयीन प्रक्रिया में स्वयं पक्षकार होंगी इसलिए उनकी जांच मानने योग्य व ग्राह्य नहीं होगी।

निष्कर्ष यह है कि तेल में मिलावट के इस खेल में स्वयं पेट्रोलियम मंत्रालय शामिल है, तो कौन रोकेगा फिर महाराष्ट्र में मिलावटी तेल माफिया ने उपजिलाधीश सोनवणे को मिट्टा का तेल डालकर आग लगा दी, बाद में ज्यादा हल्ला मचा तो उसको मारने वाले हत्या के आरोपी की भी हत्या कर दी गई, ताकि सारा मामला ठंडा किया जा सके और सोनवणे की हत्या के आरोपी की हत्या के बाद स्वाभाविक रूप से मामला ठंडा हो गया, जबकि पूरे महाराष्ट्र के हर पेट्रोल पंप पर भी मिलावटी पेट्रोल, डीजल बेचा जा रहा है।

रिलायंस के इशारे पर सारी शासकीय पेट्रोलियम कं. जानबूझकर अपने पेट्रोल पंपों पर मोटा धन डकार कर खुली छूट दे रही है। जिसमें सारे जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों से लेकर खाद्य निरीक्षकों तक भी शामिल हैं। जिसका पैसा पाइप लाइन से होता हुआ सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रालय भी सबकुछ जानकर अंजान बना हुआ है। स्वाभाविक है जनता के साथ खुली लूट को कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर केंद्रीय जांच ब्यूरो यह जांच क्यों नहीं करता कि देश का ये सबसे बड़ो पेट्रोलियम उद्योग के मालिक का 124 लाख बेरल प्रतिदिन का उत्पादन आखिर कहां जा रहा है। सरकारी अधिकारी, निरीक्षकों को भी रुपए लाख-पचास हजार प्रति माह चाहिए कहां से और कैसे आयेगा, जब तंत्र ही ढीला है तो वसूली करने में क्या बुराई है। फिर स्थानांतरण रुकवाने, जांच रुकवाने, स्थानांतरण करवाने, के लिए भी तो ऊपर धन देना पड़ता है वह कहां से आएगा, पेट्रोल रुपए 100 प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर पड़े। जनता को अपनी लड़ाई लड़नी है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी तो केवल कमाई करके कागजी खानापूर्तियों के लिए होता है। वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है।

कमीशनखोरों का चिंतनीय नाटक...

प्रथम पृष्ठ का शेष

दूसरी ओर महंगाई के तीन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वायदा व्यापार, निर्यात और बैंक ऋण जो खाद्य वस्तुओं पर किया जा रहा है। यदि तत्काल खाद्य वस्तुओं यथा तेल गुड़, शकर, गेंहू, दाल, चावल पर यदि वायदा व्यापार बंद निर्यात और बैंक ऋण देना बंद कर दिया जाए तो घोषणा के 24 घंटे के अंदर महंगाई घट जाएंगी, तीनों धूर्त सरदार मनमोहन प्रणव मुखर्जी और कृषि मंत्री शरद पंवार इन तीनों बिन्दुओं के उपर तो कोई चर्चा कमीशन खोरी ओर वसूली के चलते करना नहीं चाहते। दूसरी फालतू की बकवास पर चर्चा कर जनता और मिडिया को महंगाई पर चिंता की व्यर्थ नौटंकी करते है।

3जी स्पेक्ट्रम घोटाले में टेपकांड में मिडिया के मुखेरे श्वानों भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी व अन्य मिडिया हाउसेस की बिकाउ मानसिकता उजागर हो चुकी है। पूरा देश भर का बड़ा मिडिया हृष्य, श्रव्य और मुद्रित सत्राधीशों और पूंजी पतियों की रखैल और नीरा रांडिया जैसी अनेक जालसाजों की कठपुतली बन देश की जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी धन लिप्सा पूरी कर रहे हे। आखिर ये तीनों महंगाई के कारक तथ्यों पर क्यों प्रहार नहीं करते जो महंगाई के लिए जिम्मेदार है। पर तीनों ही तथ्य मोटे कमीशन देने वाले और पूंजीपतियों की कमाई के साधन है। इसलिए सावन रुपी कमीशन के अंधो को सब कुछ हरा हरा ही दिखता है इसलिए वो इसपर कभी कुछ बोलना ही नहीं चाहते फिर कांग्रेस के अक्षरों का अर्थ है करप्शन आरिएंटेड नोटोरिपसगेंग आफ रिसोर्सेज सकिंग सर्विसेन के अनुसार सभी स्त्रोतों से धन चूसना ही जिनका मूल उद्देश्य है। फिर कांग्रेस की मानसकता है, कि सत्ताधीश जनता को जितना शोषण करेंगे उतना ही जनता सिर और कमर झुका कर चलेगी और अपने कुकर्मों नोंच खसोंट पर निगाह नहीं उठेगा। इसलिए महंगाई से जनता की कमर और सिर झुकाया जा रहा है।

आतंक को आश्रय, शत्रु को...

प्रथम पृष्ठ का शेष

जो भविष्य में कभी भी किसी भी स्तर पर घातक होगा। इससे हिन्दु और मुस्लिम दोनों स्तर के अधिकारियों के मनोबल टूटेंगे और वे कभी भी दिल से देश की बात सेवा की बात नहीं करेंगे। ज्यादा परेशान किया गया तो सेना में बगावत का यह खुला आमंत्रण होगा।

कांग्रेस को आरएसएस से राष्ट्र भक्ति और संगठन सीखना चाहिए था, जो उसको भविष्य का ठोस आधार होकर वोट बैंक होता और उससे अच्छे नेता मिलते। इसके विपरीत एक नेहरु खानदान कितने वर्ष राज्यकर सकेगा। छलः कपट, जालसाजियां जनता के पैसे को लूटकर कब तक विदेशी व स्विस बैंकों में मरते रहोंगे फिर आरएसएस के लोगों को जितना प्रताइत करोंगे उतने ज्यादा हिन्दु उसमें जुड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस जो कि मानसिक रुप से पूर्णतः दिवालिया हो चुकी है। हर जगह उसकी नीतियों का फरेब जनता को समझ में आ रहा है। जो उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की धज्जियां निरंतर देता है। पर वे सारे बत्तमीज एक झूठ बोलते है उसे सच सिद्ध करने के उपर से 100 झूठ बोलते है परिणाम कांग्रेसी गिरोह के साथ ही सरकार को न केवल भोगना पड़ता है वरन फिर क्षति पूर्ति नियंत्रण जिसे इंग्लिश में डेमेज कंट्रोल कहते है फिर उसके लिए भी छल कपट का सहारा लेना पड़ता है। इस सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के सम्मान की तो दूर सरकारों को आंतरिक रुप से जनता के सामने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सफाई पेश करना पड़ती है।

आखिर क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का गौरव खोना चाहती है। आने वाली पीढ़ी बहुत तेज और समझदार है। वो हर चाल को बड़ी बारीकी से न केवल समझ रही है वरन बिहार जैसे राज्य में भारी पटखनी भी दे रही है। इससे भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है।

खाद्य एवं औषधि अपमिश्रण-महीना वसूली विभाग

4 निलंबन आरोप पत्र-औपचारिक मजाक-भ्रष्टों की सुरक्षा

कमाई के लिए इंदौर में भ्रष्ट औषधि निरीक्षकों का स्थानांतरण

मप्र में स्वास्थ्य विभाग और इसकी सभी शाखाएं भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रहती है। जिससे यह विभाग सदा मिडिया की सुर्ख़ियों में बना रहता है। भ्रष्ट डॉ. शरद पंडित की जालसाजियों का मात्र से 2 से 5 प्रतिशद ही प्रकाश में आया और प्रकरणों की शुरुआत हुई और रु. 25 से 50 लाख खर्च कर पुनः इंदौर में डंटा हुआ है। महीने की वसूली 400 नर्सिंग होम्स, 200 से ज्यादा वैध-अवैध पैथोलाजी लैब ब्लड बैंकस, 500 से ज्यादा क्लीनिक्स आदि से करोड़ से ज्यादा की वसूली हो जाती है। फिर पूरे इंदौर जिले के सारे प्राथमिक उपचार केन्द्रों से लेकर, शासकीय चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालय आदि की खरीदी आबंटन से रु.1 करोड़ प्रतिमाह से ज्यादा कमीशन आद बटोर लिया जाता है। इसी के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि विभाग जिसका भी ये उपसंचालक है। एक माह पूर्व ही चार खाद्य निरीक्षकों का निलंबन हुआ है, जिसमें दो खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया और अरविन्द पॅथरोल महा भ्रष्ट, जालसाज थे लंबी अवधि के कुकर्मो के बाद अब जबकि रु.2 से 5 करोड़ की अवैध संपति के मालिक हो चुके है निलंबित अवश्य किए गए। मात्र कागजी खानापुर्ति के लिए। नकली घी कांड में जिस दिनेश साहू से ये हर महीने 25000/- वसूल कर उसकी चार फैक्ट्रीयां चलवा रहा था इसी प्रकार सुभाष खेड़कर की नकली हींग पकड़ी उसे भी जब्त नहीं किया गया उसे भी रु.1 लाख लेकर छोड़ दिया गया था। तीसरा बुलाग इंटरप्राइजेस, 28 रियल स्टेट कनाड़िया रोड इंदौर के मामले में भी जिस गुप्ता ने इस नकली के घी के नमूने लिए थे। वहां पर छापे में सिवाए वनस्पति और इसेंस के एक बूंद भी बटर आइल, मक्खन या दही नहीं मिला था। जिसने पुरा प्रकरण बना कर घी की जब्ती की थी। उसकी खाद्य निरीक्षक के रुप में पदस्थत्तपना से लेकर निलंबित होने से पूर्व तक की नमूना प्रतिवेदन में मप्र में सबसे ज्यादा 35

प्रतिशत तक मिलावटी निकले उसे महाभ्रष्ट, रिश्वत खोर और हर वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा की वसूली करने वाले सचिन लोंगरिया का वसूली में अंड़गे डालने और नमूने लेने के कारण ही इस स्वा.नि. को बचाने और अच्छा काम करने, मनोबल तोड़ने के लिए, महाभ्रष्ट पूर्व के भ्रष्ट नियंत्रक ने चूंकि बुलाग से रु. 17 लाख का लेनदेन हो गया था निलंबित करवाया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र हार्डिया भी इस रु. 17 लाख के लेन देन में शामिल था।

इन चारों को दिए गए आरोपों में एक जैसे आरोप लगाए गए कि आपने नमूने निर्धारित संख्या में नहीं लिए। जबकि इन हरामखोरों नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव और संयुक्त नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव को पूरे मप्र में कार्यरत 200 से ज्यादा खाद्य निरीक्षक नहीं दिखाते जो1 माह में 10 नमूने भी नहीं लेते और जिनके नमूने 10 प्रतिशत भी अपमिश्रित नहीं पाए जाते। जबकि पूरे प्रदेश में दूध, चाय से लेकर सारे मसाले और 90 प्रतिशत खाद्य पदार्थ मिलावटी होते है। सारे खाद्य निरीक्षकों का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है महीने की वसूली जो प्रति माह लाखों रु. में होती है। अगर खा.नि. सचिन लोंगरिया से रु.5 लाख लेकर अगर इतने साधारण आरोप ही लगाने थे तो पूरे प्रदेश के सभी खाद्य निरीक्षकों को ही निलंबित किया जाना चाहिए था। फिर इंदौर के खाद्य निरीक्षकों के नमूने लेने और फेल होने, अपमिश्रित पाए जाने के साथ सबसे ज्यादा, सचिन को छोड़कर प्रकरण इंदौर में ही न्यायाय में प्रस्तुत किए गए है।

फिर बुलाग के शुद्ध नकली घी की आर एमवी 17 रु. 2 लाख लेकर, निकालने वाले लोक विश्लेषक को भी तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए था। पर उस पर तो उस श्वान खाद्य नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव ने अंगुली तक नहीं उठाई। बेशक इस षड़यंत्र का सबसे बड़ा शिकार भी हुआ कि उसे प्रकरण के चलते, विभाग से ही चलता कर दिया गया और खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के रुप में मनोहर अगनानी को पदस्थ किया गया। जिन्होंने आते ही साथ औषधि निरीक्षक गर्ग को खरगोन के साथ इंदौर का भी प्रभार दे दिया। जिस महाभ्रष्ट औ.नि. वृंदनानी की जालसाजियों, अवैध रुप से औषधि अनुज्ञात्तियों की शिकायतों, के चलते यहां से स्थानांतरित किया गया उसे नव 10 में ही इंदौर के दवा बाजार का भी काम दे दिया गया अब ये हरामखोर पूरा दवा बाजार इंदौर में अपने घर पर ही लगाकर चला रहा है। नियंत्रक का जाति भाई है वो अगनानी ये वृंदनानी दोनों ही मेड़ा सांई इंदौर में दो नए पदस्थ औषधि निरीक्षकों की अभी उचर के लगी है दोनों ही भ्रष्टाचार के फुल थ्राटल में उड़ान भर रहे है।

रिकार्ड बना रहे है औषधि करने में लगे है। यथा ठाकुर और गोयल शाम को मिलते है तो पूछते है कितनी पेटी, अंगुली के इशारों में एक ने दो दिखाई तो अगला 2 दिखा कर आधी दिखा देता है। 90 प्रतिशत दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं है। 100 प्रतिशत इंदौर की औषधि दुकानों में समय बाधित और प्रतिबंधित दवाओं जैसे नाइट्रोवेट व अन्य जैसे निमसुलाइड, मेक्साफार्म अभी तक बिक रही है। प्रतिबंधित दवाओं की सूची इंटरनेट साइट पर उपलब्ध है।

भारी भ्रष्टाचार से प्रदूषित, प्रदूषण मंडल

मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, प्रमुख सचिव से लेकर नीचे तक सब पूंजीपतियों के टुकड़खोर

म.प्र. प्रदूषण फैलाओ मंडल मंत्री, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सभी के लिये कमाई और वसूली का स्रोत बन चुका है। इस अवैध कमाई के लिए अध्यक्ष और सचिव दोनों की नियुक्तियां पूरे हरामखोर भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर पूर्व मुख्य सचिव राकेश साहनी और तात्कालीन मंत्री जयंत मलैया ने सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख समिति के निर्देश दिनांक 27.07.05 की अपेक्षाकर बिना उचित योग्यता और अनुभव को दर किनार कर अपने क्षेत्र के निहायत भ्रष्ट, जालसाज एनपी शुक्ला की म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंउल के अध्यक्ष रूप में नियुक्ति कर दी; ताकि ये भ्रष्टाचार के प्रदूषण से दोनों हाथ कमाई कर प्रदेश के पर्यावरण और जनता व उसकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से बेरोकटोक वसूली करते हुए खिलवाड़ कर सके।

पूर्व मुख्य सचिव साहनी लंबे समय तक आवास व पर्यावरण विभाग के सचिव के पर्यावरण आयुक्त भी थे, मुख्य सचिव के पद पर रहते हुये भी इस हरामखोर ने जालसाजी पूर्ण तरीके से जालसाज बी.के. सिंह को 2005 में सदस्य सचिव नियुक्त कर दिया था जिसे म.प्र. उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका क्र. 16234/2005 में दिनांक 20/06/07 को निरस्त कर दिया था। पुनः 2008 में तकनीकी शिक्षा विभाग के दूसरे जालसाज उपसंचालक आर.के. जैन की नियुक्ति सदस्य सचिव के रूप में नियम विरुद्ध तरीके से कर दी गई थी। इसके विरुद्ध भी एक जनहित याचिका क्र. 12747/009 म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है।

म.प्र. प्रदूषण फैलाओ मंडल में भ्रष्टाचार किस हद तक हर कदम फैला हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंडल के सदस्य सचिव हेतु मार्च 09, 2003 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, तब से लेकर मार्च 09, 2003 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, तब से लेकर वर्तमान तक 5 सदस्य सचिवों की बगैर साक्षात्कार के ही नियुक्ति कर दी गई, भाजपा के भुखेरे श्वानों को तो टुकड़ा दिखना चाहिए बस, इन्हें न केवल कानून से कोई मतलब नहीं वरन जनता में इस अनुशासित होने का ढोंग करने वाली पार्टी की छवि कैसे नीलाम हो रही है। इन्हें इससे भी कोई मतलब नहीं। जहां तक पूर्व मुख्य सचिव साहनी का सवाल है, ये तो भुखेरा मुख्य सचिव के पद पर 25-50 हजार करोड़ की संपत्ति पूरे भारत में अर्जित करके कई कॉलेजों, कॉलोनियों में भी पैसा लगा चुका है। इस हरामखोर जालसाज ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.657/1995 दिनांक 14/10/2003 के निर्णय की भी अवहेलना करते हुए पीथमपुर के अतिरिक्त किसी भी साइट में उद्योगों के खतरनाक अवशिष्टों को नष्ट करने में जानबूझकर भी कोई रुचि नहीं ली, जबकि यह मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व आयुक्त पर्यावरण और आवास के पद पर भी रह चुका था, इन्हीं हरामखोरों ने प्रदूषण फैलाओं मंडल में एसपी गौतम जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सदस्य म.प्र. प्रदूषण मंडल के भी अध्यक्ष रह चुका है। इनका आपराधिक प्रवृत्ति का इतिहास रहा है। इनके भ्रष्टाचार की लंबी दास्तान अनेकों समाचार पत्रों में अनेको बार प्रकाशित हुई परन्तु इसके विपरीत इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के उपरोक्त अधिकारियों क्राइम पर वरदहस्त बना रहा, इसके जालसाजी पूर्ण कृतों में प्लासिक से पेट्रोल बनाने की कपोल कालित योजना में भी रु. 30 करोड़ हजम करेगा, जिस प्लासिक से पेट्रोल बनाने की योजना नागपुर के प्लांट के आधार पर इन्होंने बनाने की रखी थी उसे केंद्रीय प्रदूषण मंडल ने मात्र प्रदर्शन संयंत्र बताकर सिरे से नकार दिया था इसके विपरीत उस समय के तात्कालीन मंत्री जयंत मलैया ने इसे आंख मींचकर स्वीकृति दिलवाई, जिस पर एशियन विकास बैंक से भी ऋण स्वीकृत होकर 30 करोड़ की किस्त भी मिल गई थी।

लोकतंत्र में सरकारी तंत्र सत्ताधीशों और पूंजीपतियों का गुलाम होता है, फिर म.प्र. में सरकार चाहे कांग्रेसियों की रही हो या भाजपाइयों की सत्ता के वास्तविक खिलाड़ी तो सारे आई.ए.एस. ही होते हैं जो इन मंत्री रूपी अक्ल के पैदलों को जैसा हांकते हैं ये वैसे ही नृत्य करते हैं। सो वही सब कुछ प्रदूषण मंडल में भी हुआ, और हो रहा है और होता रहेगा। फिर जब बात प्रदेश में दारूलाबी की हो तो उसके सामने कोई मंत्री हो संत्री हो, अध्यक्ष हो, प्रदूषण मंडल हो, आबकारी आयुक्त हो, उपनिरीक्षक हो, कांस्टेबल हो सब इनके महीने के गुलाम होते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय प्रदूषण मंडल ने प्रदेश की 12 डिसलरीस जिन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित नियमों के पालन के अभाव में कार्यवाही करने के लिए क्षेत्रीय म.प्र. प्रदूषण मंडल और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्यवाही करने के लिए लिखा परन्तु इन सभी हरामखोरों को जिसमें छोटे से वैज्ञानिक, नमूना संग्राहक से लेकर उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय, प्रदेश के अध्यक्ष जो उस समय गौतम थे और अब एन.पी. शुक्ला हैं। पर्यावरण आवास मंत्री, सचिव प्रधान सचिव से लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री तक को पैसा बंटता है। इसलिये ये हरामखोर रिवर्स आस मॉसेस प्रक्रिया जो महंगी होने के साथ रणनीति भी है, को नहीं अपना रहे हैं। जिसमें शराब उत्पादन से उत्पन्न जहरीले कचरे को रासायनिक प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। जहां तक मिस्टइवोपेरेशन या नमी वाष्पीकरण से कचरे को शुद्ध करने की प्रक्रिया का सवाल है, तो उसे भी अधिकांश ने अभी तक उपयोग नहीं किया इसके चलते रायसेन की सोम डिस्लरी, बड़नगर के पास की ओयासिस, रायरू ग्वालियर, ग्रेटन गेलियन, लेबड़ जिला धार आदि 12 डिस्टलरियों ने पिछले 20 वर्षों में सैकड़ों एकड़ जमीन और करोड़ों लीटर नदियों जिसमें नर्मदा जैसी पवित्र नदी में प्रदूषण प्रवाह से बर्बाद किया ही साथ भूजल के स्रोतों को भी भारी प्रदूषित किया, एस.पी. गौतम ने भी इनसे पैसा हजमकर न केवल इन डिस्टलरीज पर कार्यवाही तो की ही नहीं वरन उनकी रु. 1.75 करोड़ की गारंटी भी जप्त नहीं की, उल्टे ही म.प्र. आबकारी विभाग ने शासकीय डिसल्रीज को 31/3/11 से बंद कर पूरे प्रदेश में देशी शराब की आपूर्ति के ठेके भी दे दिये; हालात पहले से भी बदतर हो जायेंगे।

पीथमपुर में रेमली का इंसीनरेटर प्लांट भी केवल उद्योगपतियों से उनका औद्योगिक अवशिष्ट इक्ट्ठा कर संग्रहित किया जा रहा है और पैसा वसूला जा रहा है, जिसमें इंदौर मे चार पीथमपुर का क्षेत्रीय अधिकारी दोनों हाथों से वसूली में जुटा है और धन का वितरण वर्तमान अनुपयुक्त, अयोग्य जालसाजी से मंत्री द्वारा गृहनगर को होने के कारण नियुक्त एन.पी. शुक्ला अध्यक्ष और सदस्य सचिव आर.के. जैन के साथ मंत्री भी वसूल रहा है जिसमें प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की भी हिस्सेदारी है, जबकि यदि इंदौर के जागरूक नागरिक आंदोलन नहीं करते तो यूनियन कार्बाइड 26 वर्ष से पड़े लीक गैस के 2200 टन जहरीले अवशिष्टों को यहां लाने की भी तैयारी थी, जबकि चोरी छिपे लगभग 100 टन मिक गेस के ठोस अवशिष्टों को देवास, उज्जैन, धार के माध्यम से वहां पहुंचा भी दिया गया क्योंकि उसमें अभी भी करोड़ों रुपए का लेन-देन नष्ट करने में ही कुछ हो चुका है और कुछ होना है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, कि जून 05, में जब इसकी आधार शिला रखी जा रही थी तब ही पूरा प्रदूषण मंडल रेमली वायरो की कठपुतली बन धन लेकर नाच रहा था जो सैद्धांतिक प्लांट की संरचना थी वह 60 एकड़ की भूमि पर रु. 25 करोड़ के प्लांट पर रु. 8 करोड़ का अनुदान था अर्थात रुपए 8 करोड़ में ही सैद्धांतिक नियमानुसार प्लांट बनना था। कंपनी ने पूरे खेल में रुपए 1 करोड भी खर्च नहीं किया न ही स्तर के भस्मक लगाये, केंद्रीय प्रदूषण मंडल, सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग कमेटी भी इस आधारभूत सत्य को उजागर नहीं कर सकी है। सबको दोनों हाथों से पैसा बटोरने में लगे हैं। कौन सा कानून, कैसा कानून न ही शूकरों सचव सदस्य आर.के. जैन में योग्यता है न ही एन.पी. शुक्ला में। फिर मंत्री तो मुख्य सचिव, पर्यावरण आवास प्रधान और सचिव की कठपुतली है। मंत्री चाहे केंद्रीय हो या राज्य के सब टुकड़खोर भूखे भेड़िये होते हैं। जिन्हें आंख मींचकर बस धन बांटते रहो चाहे फिर बीस वर्षों से इंदौर में बैठा ए.ए. मिश्रा कुछ भी करे यहां तक कि ये हरामखोर भ्रष्ट जालसाज अब पत्रकारों को केंपस में भी नहीं घुसने देता, क्योंकि यहां न केवल हर कदम भ्रष्टाचार की वरन अय्याशी लूट और वसूली का हर कदम तांडव हो रहा है। क्योंकि मिश्रा रुपए 10 करोड़ हर वर्ष वसूल कर इन अधिकारियों, मंत्री और मुख्यमंत्री तक टुकड़े डालता है। बेचारे टुकड़कारे या भ्रष्टों पर गुर्राकर हटायें।

शासन बना रहा नर्मदा को जहरीला

पृष्ठ 7 का शेष

इसमें से करीब 700 एकड़ जमीन सरकारी है। करीब 75 लोगों की 300 एकड़ जमीन ली जा चुकी है। इसका निर्माण 2014 तक पूरा किया जाना है। इनके लिए विदेशों से कोयला मंगाने की तैयारी की जा रही है।

जमीन और जंगल पर संकट

थर्मल कोल पावर प्लांट से निकलने वाली राख आसपास की हजारों एकड़ जमीन की उत्पादन क्षमता को नष्ठ कर देगी। अब तक कई अध्ययनों में इस बात का खुलासा हो चुका है। सारणी स्थित सतपुड़ा पावर प्लांट से निकलने वाली राख से हजारों पेड़ नष्ठ और तवा का पानी प्रदूषित हो गया है। प्रस्तावित झासीघाट प्लांट की जद में आने वाले गांव सिलारी के किसान पुहुपसिंह ने बताया कि उन्हें कंपनी के इंजीनियर ने यह कहकर जमीन छोड़ने की सलाह दी कि प्लांट लगने के बाद इस पर राख की मोटी परत जमा हो जाएगी, तब यहां कोई फसल पैदा नहीं होगी। यह संकट करीब 20 किलोमीटर की परिधि की जमीन पर है। इससे जबलपुर के भेड़ाघाट के संगमरमर की सुंदरता को भी खतरा है। राख से हजारों पेड़, वन औषधि और चारा खराब हो जाएगा। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के साथ ही मवेशियों पर भी संकट आएगा।

दस गांवों में नहीं हो सकी शादी

तूमड़ा के रामकेश और मोहनसिंह राजपूत ने बताया कि पावर प्लांट की जद में आने वाले दस गांवों में इस वर्ष एक भी युवक की शादी नहीं हो सकी। जब रिश्तेदारी की बात आती है तो लोग यह कहकर इनकार कर देते हैं कि आपका गांव तो कभी भी उजड़ जाएगा। बेटी को डुबाना नहीं है। कमलसिंह सिकरवार और मेहरागांव के आनंद तो यह पीड़ा को कलेक्टर को भी सुना चुके हैं। इन दस गांवों की करीब 2500 एकड़ जमीन इस परियोजना से प्रभावित होगी।

वैश्विक उष्णता के बढ़ते स्तर पर प्राकृतिक

पृष्ठ 2 का शेष

विश्व स्तर पर अमेरिका अपने पाप धोने, अपने कुकर्मों को ढ़ाकने विश्व के अन्य राष्ट्रों को हड़काने विश्व स्तर पर कभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का मामला उठाता है, कभी फ्लुरों कार्बन, कभी कार्बन क्रेडिट की नौटंकी करके हल्ला भी मचाता है। कभी कानकुन सम्मेलन बुलाता है। और सबसे पहले जब स्वयं के उपर ग्रीन हाउस गैसेस के फ्लुरों कार्बन गैसेज, औद्योगिक प्रदूषण की बात उठती है। तो स्वयं किसी भी प्रतिबंध को मानने से इंकार कर देता है।

पर इस संबंध में भारत और चीन की बात उठती है तो प्रतिबंध लगाने, उद्योगों के प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए दबाव बनाता है। इसके विपरीत वास्तविकता में प्राकृतिक स्तर पर मौसम की इस उठापटक में सबसे ज्यादा वो और उसके चारों तरफ के अन्य युरोपियन देशों में गाहे-बगाहें भारी तबाही प्राकृतिक आपदाओं से ही सबसे ज्यादा आती है।

वक्त है सभी विश्वस्तर पर घटते वनों को औद्योगिक प्रदूषण को न केवल रोके वरन वनों का विकास औषधिय पेड़ों के साथ करें। दूसरी और औद्योगिक प्रदूषण बढ़ता कांक्रीट जंगल को नियंत्रित करे आखिर मानव अपने हाथ से ही अपने आप को नष्ट करने पर क्यों तुला है।

साप्ताहिक समय माया

महिला एवं बाल विकास-कार्यकर्ता, निरीक्षक, अधिकारी का स्व विकास

अरबों रु. की बर्बादी के बाद भी चारों तरफ कुपोषण से भी मौतें

सारी कागजी आंकड़ों की बाजीगरी, पैसा हजम-संयुक्त संचालक की एक रिपोर्ट

पूरे राष्ट्र में गरीब महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये केंद्रीय महिलाएंव बाल विकास मंत्रालय भी रुपए 50 से 60 हजार करोडत्र रुपए हर वर्ष खर्च करता है। साथ ही इतना ही पैसा राष्ट्र के सभी राज्यों की सरकारें भी गैर नियोजित मद में खर्च करती है, ताकि भविष्य की पीढ़ी और उनकी माताओं का संपूर्ण विकास हो सके, इसके विपरीत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग से लेकर राज्यों के महिला बाल विकास में बैठे मंत्री से लेकर सचिव, आयुक्त/संचालक, जिलों में बैठे धूर्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों से लेकर, एकीकृत बाल विकास अधिकारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक विशुद्ध 90% धन कागजी आंकड़ों की कार्यवाही कर डकारा जा रहा है। अकेले म.प्र. की आबादी को हम 07-08 में 7 करोड़ भी मान लें तो 7 करोड़ की आबादी में 78929 आंगनवाड़ियां थीं जिसे 79 हजार लेकर चलें और एक आंगनावाड़ी में औसतन 70 से 80 बच्चे होते हैं।

जो कि 90% फर्जी होते हैं। यह संयुक्त संचालक की निरीक्षण रिपोर्ट भी सिद्ध करती है। अर्थात 63 लाख 20 हजार बच्चों के नाम से शासन की 10 से 12 योजनाओं का रुपए 400 से 500 करोड़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जिनकी संख्या अकेले प्रदेश में 453 है और पूरे देश में लगभग 15000 से ज्यादा के अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से लेकर संयुक्त संचालक, संचालक, सचिव और मंत्री तक पूरा हजम कर जाते हैं। जब सभी आंगनवाडत्री कार्यकर्ता से लेकर पर्यवेक्षक, अधिकारी, बाबू, कर्मचारी तक सारी कागजी खानापूर्तियों रुपए .25 हजार प्रति माह से लेकर रुपए 10-20 लाख प्रति माह डकार रहे हों, हर महीने कुल मासिक आवंटन का विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का धन आवंटित होता है उसका वास्तविक जो कि 5 से 10% के बीच होता है उसका 50% धन तात्कालिक वरिष्ठ के पास 50% लौटता है। जैसे कि एक एकीकृत बाल विकास अधिकारी के पास 50 आंगनवाड़ियां हैं प्रत्येक में औसतन 80 बच्चे हैं और 100 मातायें हैं। प्रत्येक माह विभिन्न योजनाओं में रुपए 1 लाख मिला, खर्च मात्र रुपए 5 से 8 हजार दिखाने के लिए, रुपए 90,000 में से रुपए 45000 प्रत्येक आंगनवाड़ी से आईसीडीएस अधिकारी के पास लौट आएगां आईसीडीएस अधिकारी के पास रुपए 22.50 लाख में से रुपए 11.25 लाख मिला। कार्यक्रम अधिकारी के पास आईसीडीएस अधिकारी बेईमानी के इस पैसे से कोई ईमानदारी से भेंट करदेगा, अब जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास 10 आईसीडीएस अधिकारी हैं तो उसके पास रुपए 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार जो इकट्ठा होगा उसका रुपए 10 लाख स्टॉफ में पद और दम के हिसाब से जिला कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को बंट जाएगा रुपए 1 करोड़ में से रुपए 50 लाख सीधे मुख्यालय तक संचालक के पास पहुंचेगा, उसके पास 50 जिलों में से रुपए 25 करोड़ में से सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव को मंत्री और मुख्यमंत्री को रुपए 15 करोड़ में से हिस्सा बंट जाएगा। यह गणित ऊंचा नीचा 10 से 20% का जोड़ घटाना हो जाता है। कागजों पर 95% फर्जी जमा खर्च हो जाता है।

यही कारण है कि इंदौर की संयुक्त संचालक ने जो निरीक्षण किये उसमें जानबूझकर जालसाजी पूर्ण तरीके से जांच की गई, जैसे आंगनवाड़ी की बच्चों की संख्या, पंजी में क्या है नहीं लिखी गई, महिलाओं की संख्या पंजी में क्या है और कितनी केंद्र पर आती है या तेल, नमक, गुड़, ईंधन कितनों को दिया जाता है कुछ नहीं लिखा गया है। आखिर भ्रष्टों की उसी कड़ी की ये भी एक श्रृंखला है। इसने भी औपचारिकताएं पूरी की हैं। इसके उपरांत भी वर्षों गुजरने के बाद भी तत्काल किसी भी आंगनवाडत्री को न तो निलंबित किया जाता है, न हटाने की कार्यवाही, लूट, भ्रष्टाचार और शासकीय धन की डकैती में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर मुख्य सचिव और मंत्री तक सभी बंटोरने में लगे हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण टीनू जोशी प्रधान सचिव पर पड़े छापे से सामने है। बच्चों की कुपोषण से मौतों के यही कारण हैं। अरबों रुपए ऐसे ही हजम किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ की भारतीय बच्चों के संदर्भ में 15% शहरी और 50 % ग्रामीण बच्चे कुपोषित हैं। इनी मक्कारी भ्रष्ट डकैतों के कारण ही बनी हैं। सं. सं. इंदौर संस्था व्यास की रिपोर्ट के अंश-

दिनांक 14.9.2010 को आपके जिले की देपालपुर परियोजना के आंगनवाड़ी केंद्रों का अवलोकन किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र का समय सारणी अनुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। वार्ड क्र. 7 देपालपुर की आंगनवाड़ी में रिकार्ड सधारण, संचालन की स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की है। पोषण आहार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है।

पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाना प्रतीत हो रहा है। मानदेय एंव मंगल दिवस की राशि समय पर कार्यकर्ता के खाते में जमा नहीं की जा रही है। समस्त सर्वेक्षित बच्चों का वजन नहीं लिया जा रहा है। कतिपय आंगनवाड़ी केंद्रों के अतिरिक्त अन्य केंद्रों में वजन संबंधी रिकार्ड अद्यतन नहीं किये गये हैं। गृह भेंट व्यवस्थित नहीं की जा रही हैं

विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन पत्र के संलग्न प्रेषित किया जा रहा है तद्नुसार संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पर आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से एक सप्ताह की समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 14.9.2010 को आपके जिले की सॉवेर परियोजना की आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार स्थितियां पायी गईः-

1. आंगनवाड़ी केन्द्र बड़ोली होज :- प्रातः 10.45 पर आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाया गया। केंद्र की स्थिति देख कर ऐसा लगता है कि विगत कई दिनों से केंद्र खुला ही हनीं।

2. आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड क्र-7

- प्रातः 11 बजे निरीक्ष्ज्ञण के समय केंद्र पर कुल 4 बच्चे उपस्थित।

- 21 जुलाई 2010 के बाद से उपस्थिति पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया।

- पर्यवेक्षक द्वारा 20 मई 2010 के बाद निरीक्षण किया जाना नहीं पाया गया।

- मंगल दिवस मनाये जाने की व्यवस्थित जानकारी कार्यकर्ता को नहीं थी। निरीक्षण दिवस मंगलवार को कार्यकर्ता द्वारा 1 वर्ष के बच्चे का अन्नप्राशन करवाया जाना बताया गया।

- वजन पंजी में अप्रैल 2010 के बाद वजन किया जाना नहीं पाया गया।

- टेक होम वितरण पंजी में जून 2010 के बाद इन्द्राज नहीं किया गया।

- केंद्र पर नाश्ता हलवा व भोजन-खीर पूड़ी रखा हुआ था जो कि अत्यंत कम मात्रा में था।

- कार्यकर्ता कार्य के प्रति सजग नहीं थी।

3. आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड क्र.-6

झ प्रातः 11.45 बजे निरीक्षण के समय केंद्र पर 25 बच्चे उपस्थित।

- केंद्र पर प्री स्कूल गतिविधियां संचालित थी कार्यकर्ता उत्साह से कार्य कर रही थी।

- केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में भोजन-खीर पूड़ी रखी हुई थी।

- मंगल दिवस मनाये जाने की तैयारी की गई थी, अन्नप्राशन के लिए बच्चें केंद्र पर उपस्थित थे।

- मंगल दिवस की राशि परियोजना कार्यालय से जमा नहीं हुई थी।

- मानदेय मई 2010 तक का जमा किया जाना बताया गया।

4. आंगनवाड़ी केंद्र बीरगोदा -

- मध्यांह 12 बजे केंद्र पर 14 बच्चे उपस्थित।

- वजन मशीन की अनुपलब्धता के बाद भी केंद्र पर 98 बच्चों का वजन लिया जाना बताया गया जिसका ग्रोथ रजिस्टर में इन्द्राज पाया गया।

- केंद्र पर टीकाकरण किया जा रहा था।

- मंगल दिवस की राशि जमा नहीं की गयी।

5. आंगनवाड़ी केंद्र गोकलपुर-

- मध्यांह 12.30 बजे केंद्र पर 14 बच्चे उपस्थित।

- केंद्र पर पर्यवेक्षक श्रीमती सुरेखा जैन उपस्थित थीं।

- मंगल दिवस की राशि जमा नहीं।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय माह जून 2010 तक का जमा होना बताया गया।

- केंद्र अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के 248 बच्चे पंजीकृत बताये गये। कव्हर्ड जनसंख्या 2500 है। पर्यवेक्षक द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त केंद्र के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

- एमपी एग्रो से प्राप्त राशन बच्चों की संख्या अनुसार प्राप्त न होने से कम पड़ता है।

6. आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड क्रमांक 12 नई आबादी गौतमपुरा-

- 0 से 5 वर्ष के 168 बच्चे सर्वेक्षित। वचन मात्र 51 बच्चों का ही लिया गया।

- केंद्र पर अतिकम वजन के बच्चों की संख्या मात्र 2 ही बतायी गयी जो कि मानक से अत्यंत कम है।

- गृह भेंट पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है।

- कार्यकर्ता सहायिका का मानदेय अनिमित है व सहायिका को प्राप्त होने वाले मानदेय का विवरण भी नहीं पता कि कब कितना मानदेय मिल रहा है।

7. आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड क्रमांक 6 नई आबादी गौतमपुरा-

- मध्यांह पश्चात 1.45 पर केंद्र का अवलोकन किया गया, केंद्र बंद पाया गया।

- कार्यकर्ता श्रीमती किरण हजारे से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की गयी मंगल दिवस पर भोजन खीर पूड़ी आना बताया गया व थर्ड मील के लिए समूह द्वारा मूंगफली दाना 1 किलो, शक्कर डेढ़ किलो, मिल्क पावडर आधा किलो व पेराशूट 50 ग्राम दिया जाना बताया गया।

- केंद्र पर 0 से 5 वर्ष के 140 बच्चे पंजीकृत बताये गये।

- एमपी एग्रो से प्राप्त होने वाले पोषण आहार कम पड़ता है। कार्यकर्ता द्वारा मात्रा बढ़ाये जाने की मांग की गयी है।

परियोजना देपालपुर के आंगनवाड़ी केंद्रों के अवलोकन सह निरीक्षण से स्पष्ट है कि -

आंगनवाड़ी केंद्र का समय सारणी अनुसार संचालन नहीं किया जा रहा है।

- वार्ड क्र. 7 देपालपुर की आंगनवाड़ी में रिकार्ड संधारण, संचालन की स्थिति अत्यंत निम्न स्तर की है। पोषण आहार भी पर्यापत मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाना प्रतीत हो रहा है।

- मानदेय एवं मंगल दिवस की राशि समय पर कार्यकर्ता के खाते में जमा नहीं की जा रही है।

- समस्त सर्वेक्षित बच्चों का वजन नहीं लिया जा रहा है।

- कतिपय आंगनवाड़ी केंद्रों के अतिरिक्त अन्य केंद्रों में वजन संबंधी रिकार्ड अद्यतन नहीं किये गये हैं।

- गृह भेंट व्यवस्थित नहीं की जा रही है।

दिनांक 29.9.2010 को संयुक्त संचालक महिला एंव बाल विकास इंदौर संभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न स्थितियां पायी गईं।

1. आंगनवाड़ी केंद्र दुधी परियोजना धरमपुरी जिला धार- समय 10.45 पर आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया गया। 03 बच्चे उपस्थित थे। कार्यकर्ता अनुपस्थित सहायिका उपस्थित थी। नाश्ते में खिचड़ी देना बताया गया। वजन मशीन उपलब्ध है। टीएचआर उपलब्ध है। केंद्र का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा रहा है।

(सेक्टर पर्यवेक्षक बबली)

2. आंगनवाड़ी केंद्र धामनोद इन्द्रानगर- 10 बजे आंगनवाड़ी केंद्र अवलोमन करने पर बंद पाया गया।

3. आंगनवाड़ी केंद्र धामनोद गुलजारा- समय 11.10 पर केंद्र पर 12 बच्चें उपस्थित थे। जिसमें से कुछ बड़े भी थे। कार्यकर्ता ने बताया कि समूह द्वारा नाश्ता एवं खाना एक साथ 10.30 बजे दिया जाता है। बच्चों को 11.15 बजे तक नाश्ता नहीं दिया गया था। कार्यकर्ता ने नाश्ता एवं भोजन एक साथ देने का बताया जो कि उचित नहीं है। केंद्र पर उपलब्ध रोटी की गुणवत्ता अच्छी नही थी। खिचड़ी की मात्रा भी 1.500 से 2 कि.ग्राम थी। केंद्र समय सारणी के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा है। बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। जबकि क्षेत्र में बच्चों की सख्या अधिक है।

(सेक्टर पर्यवेक्षक प्रमीला)

4. आंगनवाड़ी केंद्र डहीबर- समय 11.30 बजे केंद्र अवलोमन किया गया। केंद्र पर साज सज्जा नही की गई। जबकि भवन अच्छा है। कार्यकर्ता ने बताया कि समूह प्रतिदिन चावल की खिचड़ी ही देता है। जिसकी मात्रा भी बहुत कम लगभग 500 ग्राम होती है। खाना भी 10-15 बच्चों को ही दिया जा रहा है। कार्यकर्ता ने बताया कि अभी तक उसने कोई उपस्थिति प्रमाणित नहीं की है। फिर समूह को राशि का भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है। टीएचआर उपलब्ध है। सहायिका अनुपस्थित थी।

(सेक्टर पर्यवेक्षक बबली डाबर)

5. आंगनवाड़ी केंद्र मातन्दा परियोजना महेश्वर जिला खरगोन- समय 12 बजे अवलोकन के समय 3 बच्चे उपस्थित थे। जो खिलौनों से खेल रहे थे। कार्यकर्ता ने बताया कि बच्चे नाश्ता करके चले गये हैं अब खाने के समय पुनः आ जायेंगे। यह स्थिति ठीक नहीं है। नाश्ते में हलुआ दिया गया। कार्यकर्ता निर्मला कन्हैयालाल ने बताया सहायिका का पद पिछले 8 माह से रिक्त है। समय सारणी अनुसार केंद्र संचालित नहीं किया जा रहा है।

(सेक्टर पर्यवेक्षक सरस्वती सोनी)

6. आंगनवाड़ी केंद्र लाडवी- समय 12.30 बजे बच्चे अनुपस्थित थे। कार्यकर्ता सरिता यादव ने 15 बच्चों को नाश्ता देने का बताया। खाने में सब्जी, रोटी दी गई। भोजन चख कर देखा गया, गुणवत्ता अच्छी थी। 75 बच्चों का वजन लिया गया इसमें 6 बच्चे, मध्यम कम वजन के तथा 2 बच्चे अति कम वजन के बताये गये। केंद्र समय सारणी के अनुसार संचालित नहीं किया जा रहा है।

7. आंगनवाड़ी केंद्र नवलपुरा द्वितीय -

समय 12.45 पर बच्चे अनुपस्थित थे। कार्यकर्ता ने 15 बच्चों भोजन देने का बताया। 136 बच्चों का वजन लिया गया इसमें 20 बच्चे मध्यम कम वजन के तथा 2 बच्चे अति कम वजन के बताये गये। 6 माह से मंगल दिवस की राशि जमा नहीं की गई। समय सारिणी अनुसार गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(सेक्टर पर्यवेक्षक तारा वर्मा)

8. आंगनवाड़ी केंद्र गंगाझीरा मण्डलेश्वर -

समय 1.15 केंद्र अवलोकन किया गया। केंद्र व्यस्थित होकर तथा साज सज्जा पूर्ण था। कार्यकर्ता ज्योति सोपरा ने बताया कि 135 बच्चों का वजन लिया गया इसमें 45 बच्चे मध्यम वजन के तथा 8 बच्चे अति कम वजन हैं। रिकार्ड उपलब्ध था। कार्यकर्ता को केंद्र संचालन की अच्छी जानकारी है।

निरीक्षण प्रतिवेदन

डॉ. संध्या व्यास संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास इंदौर संभाग इंदौर द्वारा दिनांक 1.09.2010 को आकस्मिक रूप से निम्न आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया गया जिसमें निम्नानुसार स्थिति पायी गयी।

आंगनवाड़ी केंद्र मारुति नगर- प्रातज्ञ 11.15 बजे आंकनवाड़ी केंद्र का अवलोकन किया गया। केंद्र पर 10-12 बच्चे उपस्थित थे। कार्यकर्ता शालिनी वर्मा तथा सहायिका ललिता सोलंकी के द्वारा बच्चों का वजन लिया जा रहा था। केंद्र पर उपस्थिति पंजी, वजन पंजी, पोषण आहार पंजी का रिकार्ड संधारण व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। केंद्र पर बच्चों के माता-पिता स्वतः ले कर आ रहे थे।

समुदाय में वृद्धि निगरानी के प्रति अत्यंत जागरूकता देखने को मिली। केंद्र पर 7-8 बच्चे मध्यम कुपोषित श्रेणी के बताये गये तथा अति कुपोषित श्रेणी के बच्चें नहीं हैं। अवलोकन में प्रतीत हुआ कि कार्यकर्ता व सहायिका समर्पित भाव से कार्य कर रही है एवं पर्यवेक्षक वीणा श्रीवास्तव का मार्गदर्शन अच्छा है। मारुति नगर जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों, जहां कुपोषण कम है कि कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का उपयोग अधिक कुपोषण वाले क्षेत्रों में साप्ताहिक गहन परामर्श/ लक्षित गृह भेंट अभियान चलाकर अथवा इन क्षेत्रों में पोषण शिविर का आयोजन कर किया किया जा सकता है। परियोजना अधिकारी इस संबंध में कार्यवाही कर फीड बैक दें।

हर मोहल्ले में हो जिम, इंडोर आउट डोर खेल व्यवस्था

पृष्ठ 8 का शेष

ताकि हर बस्ती में, कालोनी में, सार्वजनिक बगीचों की, सामुदायिक भवनों की व्यवस्था, के साथ ही इंडोर, आउटडोर, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, जनता को तन-मन से स्वास्थ्य और स्फूर्त बनाए रखने के लिए सार्वजनिक व्यायाम शालाए, योग केन्द्र, हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट के साथ जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बालीबाल, बास्केअ बाल, बेटमिंटन आदि खेलने की व्यवस्थाएं भी हो। वर्ष में दो-तीन बार छोटी बड़ी स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी वार्ड स्तर पर नगर स्तर पर नगर पालिकाएं, निगम खेल मंत्रालय के सहयोग से करवाएं। निःसंदेह पहले दो-तीन वर्ष बड़ा बजट लगेगा। परंतु जनता के स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाला बजट तीसरे वर्ष से कम होने लगेगा। इन केन्द्रों की स्थापना के 5 वे वर्ष के बाद। स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला कुल खर्च आधा हो जाएगा। और खेल केन्द्रों के विकास पर हुआ कुल पूंजी, तीसरे वर्ष से हर क्षेत्र में इस पूंजी खर्च का कई गुना ज्यादा का लाभ पूरे देश को देने लगेगा। इससे हर क्षेत्र में जनता की सकरात्मक सोच का लाभ देश के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने, ग्रामीणों में नई सोच विकसित करने, अच्छी कृषि पैदावार बढ़ाने में भी सहायक होगा।

यह कार्य ज्यादा पूंजी निवेश भी नहीं चाहता पर यह अवश्य है, कि प्रशासन और चुने हुए जन प्रतिनिधियों की ठोस इच्छा शक्ति अवश्य चाहता है। एक बार शुरुआत होने पर वर्षभर में ही चारों तरफ से बेहतर परिणामों को सामने ही देख जा सकेगा । बेशक डॉक्टरों के लिए बड़े घाटे का सौदा होगा।

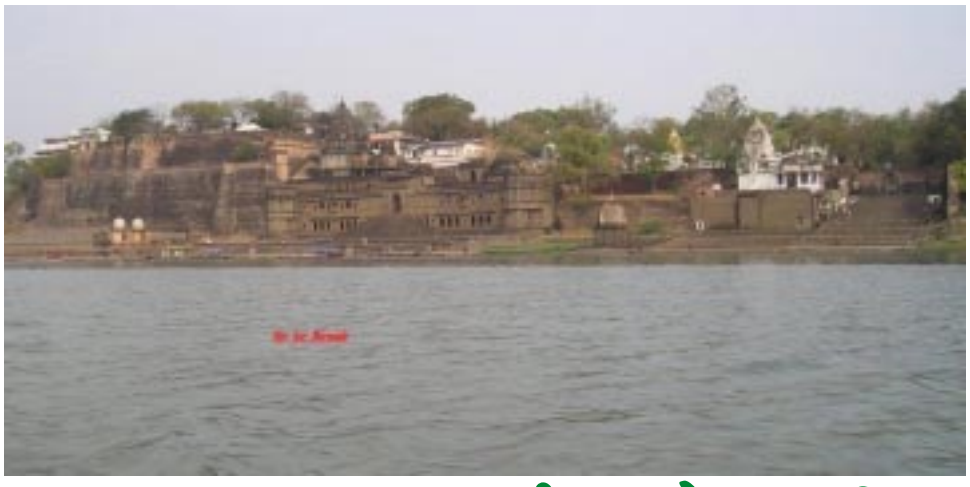

शासन बना रहा नर्मदा को जहरीला

म.प्र. में तमाम शोध और अध्ययन बताते हैं कि नर्मदा को लेकर बनी योजनाओं से दूरगामी परिणाम सकारात्मक नहीं होंगे। भयंकर परिणामों के बावजूद 'नर्मदा समग्र्य अभियान वाली हमारी सरकार नर्मदा जल में जहर घोलने की तैयारी क्यों कर रही है?

मध्यप्रदेश की जीवनरेखा नर्मदा अगले 10-12 सालों में जहरीली हो जाएगी। अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक करीब 18 थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी है। जबलपुर से होशंगाबाद तक पांच पावर प्लांट को सरकारों ने मंजूरी दे दी है। इनमें सिवनी जिले के चुटका गांव में बनने वाला प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर भी शामिल है। यह बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में है। परमाणु ऊर्जा का मुख्य केंद्र रहा अमेरिका अब परमाणु कचरे का निष्पादन नहीं कर पा रहा है। इसके बावजूद भारत में इन परियोजनाओं से निकलने वाले परमाणु कचरे की निष्पादन की बात सर?रें नहीं कर रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए नर्मदा का पानी देने का करार हुआ है। नरसिंहपुर के पास लगने वाले पावर प्लांट की जद में आने वाली जमीन एशिया की सर्वोत्तम दलहन उत्पादक है। कोल पावर प्लांट के दुष्परिणामों का अंदाजा सारणी के आसपास जंगल और तवा नदी के नष्ठ होने से लगाया जा सकता है। इतने भयंकर परिणामों के बावजूद 'नर्मदा समग्र्य अभियान वाली हमारी सरकार नर्मदा जल में जहर घोलने की तैयारी क्यों कर रही है ?

दो हजार हैक्टेयर में बनने वाले चुटका परमाणु पावर प्लांट की जद में 36 गांव आएंगे। इनमें से फिलहाल चुटका, कुंडा, भालीबाड़ा, पाठा और टाडीघाट गांव को हटाने की तैयारी है। निर्माण एजेंसी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन और स्थानीय प्रशासन इस बाबत नोटिस दे चुका है। 1400 मेगावाट क्षमता के दो रिएक्टर वाले इस प्लांट में 100 क्यूसेक पानी लगेगा। एक अनुमान के मुताबिक चुटका परमाणु पावर प्लांट में जितना पानी लगेगा, उससे हजारों हैक्टेयर खेती की सिंचाई की जा सकती है। परमाणु बिजली के संयंत्र के ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल? किया जाता है। इसकी रेडियोधर्मिता के दुष्परिणाम जन, जानवर, जल, जंगल और जमीन को स्थायी रूप से भुगतने पड़ते हैं। इसका अंदाजा रावतभाटा परमाणु संयंत्र की अध्ययन रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक परमाणु कचरे की उम्र 2.5 लाख वर्ष है। इसे नष्ठ करने के लिए जमीन में गाड़ दिया जाए तो भी यह 600 वर्ष तक बना रहता है। इस दौरान भूजल प्रदूषित करता है। चुटका में प्लांट बनने से नर्मदा व सहायक नदियों के प्रदूषित होने की आशंका है। इतना ही नहीं, भूकंप की आशंका भी बढ़ जाती है। वहीं, चुटका में निर्माण एजेंसी अपनी आ?सीय कॉलोनी प्लांट से करीब 14 किलोमीटर दूर बना रही है। प्लांट के लिए भूमि सर्वे और भूअर्जन की कोशिश जारी है, लेकिन आदिवासी और मछुआरे हटने को तैयार नहीं हैं। दरअसल ये सभी बरगी से विस्थापित हैं। हालांकि कंपनी के इंजीनियर करीब 40 फीट गहरा होल करके यहां की मिट्टी और पत्थरों का अध्ययन कर चुके हैं।

परमाणु कचरा बरपाएगा कहर

राजस्थान में चंबल नदी पर बने 220 मेगावाट के रावतभाटा परमाणु बिजली घर के 20 साल बाद आसपास के गांवों की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु बिजली घर से होने वाले प्रदूषण के घातक परिणाम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। संपूर्ण क्रांति विद्यालय बेड़छी, सूरत की इस रिपोर्ट के मुताबिक आसपास के गांवों में जन्मजात विकलांगता के मामले बढ़े हैं। प्रजनन क्षमता प्रभावित होने से निसंतान युगलों की संख्या बढ़ी है। हड्डी का कैंसर, मृत और विकलांग नवजात, गर्भपात और प्रथम दिवसीय नवजात की मौत के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं लोगों की रो? प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हुई है। जन्म और मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर सामने आया कि यहां औसत आयु करीब 12 वर्ष कम हो गई है। लंबे अर्से का बुखार, असाध्य त्वचा रोग, आंखों के रोग, कमजोरी और पाचन संबंधी गड़बड़ियां भी बढ़ी हैं। इन 20 वर्षों में बारिश के दिनों में हवा में सबसे अधिक प्रदूषण छोड़ा गया। इससे इन गांवों का पानी भी काफी प्रदूषित हो गया है। 220 मेगावाट के प्लांट से 20 सालों में यह स्थिति बनी है, जो 1400 मेगावाट के चुटका प्लांट से करीब 10 साल में निर्मित हो जाएगी। एक अन्य अध्ययन रिपोर्ट के म?ताबिक कंपनियां जितना दावा करती हैं उतना उत्पादन किसी भी पावर प्लांट से नहीं हुआ है। वहीं, इस दावे के मुताबिक जंगल और कृषि भूमि स्थायी रूप से नष्ठ की जा चुकी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 मेगावाट तक की परियोजनाओं की निगरानी केंद्र और राज्य सरकारें नहीं करती है, जिससे ये गड़बड़ियां और बढ़ जाती हैं। उक्त अध्ययन से जुड़ी पर्यावरणविद संघमित्रा देसाई का कहना है कि परमाणु बिजली घरों में यूरेनियम और भारी पानी के इस्तेमाल से ट्रीसीयम (ट्रीटीयम) निलकता है। यह हाईड्रोजन का रूप है। यह खाली होता है तो उड़कर हवा में म?ल जाता है। पानी के साथ होने पर जल प्रदूषित करता है। मानव शरीर इसे हाइड्रोजन के रूप में ही लेते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा यूरिन के जरिए निकल जाता है, लेकिन जब यह किसी सेल में फंस जाता है तो कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। रेडियो एक्टिविटी से पेड़ों को नुकसान होता है। परमाणु कचरे को नष्ठ करना मुश्किल काम है। यह हजारों वर्ष तक बना रहता है। अमेरिका इस समस्या से जूझ रहा है।

पर्यावरणीय खतरा

थर्मल कोल पावर प्लांट से निकलने वाली राख से पानी इतना प्रदूषित हो जाएगा कि इसे मवेशी भी नहीं पी सकेंगे। 500 मेगावाट के सारणी स्थित सतपुड़ा थर्मल कोल पावर प्लांट से निकलने वाली राख से तवा नदी का पानी इसी तरह प्रदूषित हो चुका है। इसमें नहाने पर लोगों की चमड़ी जलती है और त्वचा रोग हो जाते हैं। इसकी राख के निस्तारण के लिए हाल ही हजारों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, जबकि पहले से नष्ठ किए गए जंगल की भरपाई नहीं की जा सकी है। इतने दुष्परिणामों के सामने आने के बावजूद मध्यप्रदेश में देवी स्वरूप नर्मदा के किनारे थर्मल को? पावर प्लांट की अनुमति देना जनहित में नहीं है। नर्मदा में लाखों लोग डुबकी लगाकर पुण्य का अनुभव करते हैं। उनकी रूह भी इस पानी में नहाने के नाम से कांप उठेगी। राख से नर्मदा की गहराई पर भी असर होगा। वहीं गंगा के जहरीले होने के कारण सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि इसके किनारे अब ऐसा कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, तो नर्मदा की चिंता क्यों नहीं की जा रही है?

थर्मल पावर प्लांट

नर्मदा के किनारे चार थर्मल पावर प्लांट को भी मंजूरी मिली है। सिवनी जिले की घनसौर तहसील के गांव झाबुआ में बनने वाले प्लांट की क्षमता 600 मेगावॉट होगी। निर्माण एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक इसमें प्रतिघंटा छह सौ टन कोयले की खपत होगी, जिससे 150 टन राख प्रतिघंटा निकलेगी, जबकि हकीकत यह है कि कोयले से 40 प्रतिशत राख निकलती है। इस तरह करीब 250 टन राख प्रतिघंटा निकलेगी। इसका निस्तारण जंगल और नर्मदा किनारे किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय संकट पैदा होना तय है। दूसरा कोल पावर प्लांट नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा तहसील के?तूमड़ा गांव में एनटीपीसी द्वारा बनाया जाएगा। 3200 मेगावॉट क्षमता के इस प्लांट से नौ गांवों के किसानों की जमीन पर संकट है। इसके लिए करीब चार हजार हैक्टेयर जमीन ली जानी है, जबकि पास ही तेंदूखेड़ा ब्लाक में करीब 4500 एकड़ सरकारी जमीन खाली पड़ी है। इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्लांट की जद में आने वाले गांवों की जमीन एशिया में सबसे अच्छी दलहन उत्पादक है। तीसरा 1200 मेगावॉट क्षमता का थर्मल कोल पावर प्लांट जबलपुर जिले के शहपुरा भिटोनी में बनाया जाना है। इसका निर्माण एमपीईबी द्वारा किया जाएगा। इसका सर्वे किया जा चुका है। इसकी जद में करीब 800 किसानों की जमीन आ रही है। चौथा थर्मल पावर प्लांट नरसिंहपुर जिले के झासीघाट में मैसर्स टुडे एनर्जी द्वारा 5400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। 1200 मेगावॉट क्षमता वाले इस प्लांट के लिए 100 एकड़ जमीन की जरूरत है। **(शेष पृष्ठ 5 पर)**

नेशनल हाइवे लूट अथॉरिटी ऑफ इंडिया-डकैत है कमलनाथ

अंधों की रेवड़ी की तरह बांटे रा.रा. के बीओटी ठेके

सूचना अधिकार में गोलमाल जवाब, अधिकारियों की बपौती है रिकार्ड
रु. 1 करोड़ की लागत की सड़कें रु. 16 करोड में लूट के ठेकेदारों को गिरवी कर वसूला जायेगा जनता से

भारत में केंद्र सरकार में बैठे महाजालसाजों, धूर्त डकैतों का गिरोह राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोतों से लेकर जनता तक को हर तरीके और कोनों से केवल लूट और वसूली में लगा है, जिसके बारे में समय अपने शैशवकाल से बड़े स्पष्ट और सटीक अंदाज में प्रस्तुति देता आ रहा है। इसी संदर्भ में आगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही ठेकेदारों की बीओटी के अंतर्गत चल रही प्रतिदिन अरबों रु. की डकैती पर कुछ सटीक तथ्य-

केंद्र शासित दिल्ली में मेहरोली से गुड़गांव सात किमीत्र की सड़क अप्रैल 2010 में दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने 6 लेन सडत्रक मात्र रु. 8.4 करोड़ में बनाकर पूरी कर दी थी। पूरी हो जाने के बाद इन डकैतों राष्ट्रीय राजमार्ग लूट प्राधिकरण ने पुनः इसी बनी बनाई सड़क पर रु. 109 करोड़ का इस्टीमेट तैयार कर दिया जिसमें बस साइकल ट्रक और फूटपाथ और जोड़ दिया और समय सीमा अनिर्धारित छोड़ दी गई; अब यदि रा.रा. लूट प्राधिकरण का ठेकेदार रु. 109 करोड़ में सड़क को ठेके पर लेगा तो क्या बनायेगा मात्र फुटपाथ और साइकल ट्रेक जबकि वहां उसी राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री कमलनाथ का बंगला है इसलिए जमीन के अभाव में ठेकेदार ने काम अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सायकल ट्रेक और फुटपाथ बनाने पर ज्यादा से ज्यादा खर्च दिल्ली दरों पर भी निकालें तो रु. 25 लाख प्रति कि. 6 लेन तो पहले से ही बनी हुई है। अर्थात प्रति किमी. रु. 15 करोड़ 55 लाख में से ठेकेदार रु. 55 लाख प्रति किमी. भी खर्च नहीं करेगा और 25 वर्ष तक रु. 109 करोड़, ब्याज और रखरखाव के मान से जनता से वसूली करेगा; अर्थात रु. 109 से 12 करोड़ किमी. के हिसाब से कमीशन डकारा गया। दूसरी ओर नेशनल रोड कांग्रेस और भूतल परिवहन मंत्रालय हर दो-तीन वर्ष में दरों की अनुसूची तैयार करते हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय केंद्रीय सड़क निधि का पैसा राज्यों को इसी एसओआर के आधार पर बनाये गये डीपीआरया सड़कों के इस्टीमेट को आधार बनाकर स्वीकृत किया जाता है; वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पिछले दस वर्षों से रु. 25 लाख, एकहरी सड़क चौड़ाई 5 मी. दोहरी 10 मी. रु. 50 लाख स्वीकृत किये जा रहे साथ ही सड़कें भी 3 वर्ष की गारंटी में बनाई जा रही हैं। जबकि दूसरी ओर वही राष्ट्रीय राजमार्ग डकैत प्राधिकरण निजी बीओटी में रु. 15 से रु. 17 करोड़ में सड़कें गिरवी कर ठेकेदारों के साथ 50 से 80% कमीशन डकारा इस तात्कालीन भूतल परिवहन मंत्री कमलनाथ ने पूरे भारत में 70000 किमी. से ज्यादा सड़कों पर रु. 7 लाख करोड़ के खर्च का प्रावधान है। अर्थात यदि सड़कों की वर्तमान वास्तविक निर्माण 4 लेन रु. 2 करोड़ प्रति किमी. और सिक्स लेन रु. 3 करोड प्रति किमी. भी मान लें, तो भी प्रति किमी. रु. 10 से रु. 12 करोड़ विशुद्ध कमीशन ठेकेदार से डकार कर ये सारे हरामखोर भूतल परिवहन मंत्री डकैत कमलनाथ, उसका प्रधान सचिव, सचिव, रा.रा. डकैत प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, वहां बैठे डकैत इंजीनियरों से लेकर प्रदेश स्तर पर बैठे परियोजना कार्यान्वयन के महाप्रबंधक और प्रबंधक भी अरबों रु. डकार लेंगे।

यहां भी करीब रु. 4.50 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ अगले दो तीन वर्षों में डकार लिये जायेंगे क्योंकि रु. 7 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ अगले दो तीन अगले दो तीन वर्षों में डकार लिये जायेंगे क्योंकि रु. 7 लाख करोड़ की सड़कों में वास्तविक खर्च वर्तमान दरों पर रु. 2 करोड़ से 3 करोडत्र रु. प्रति किमी. ही है जबकि यह डकैत प्राधिकरण रु. 10 करोड़ से रु.16 करोड़ तक के इस्टीमेट तैयार करवाकर सड़कों को बीओटी ठेकेदारों की गिरवी कर रहा है, जबकि इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग दो लेन और 4 लेन तो पहले से है ठेकेदारों को मात्र 2 लेन बनी हुई सड़कों पर ही आजू-बाजू में बनाना है जिसका खर्च मात्र रु. 1 से 2 करोड़ ही आयेगा अधिकतम, साथ भूमि अधिग्रहण का कार्य स्वयं केंद्र शासन ही भुगतान कर रहा है तो फिर रु. 8 से 12 करोडत्र प्रति किमी. की अधिक दरों पर सड़कें जानबूझकर किस कारण से बेंची जा रही है और क्यों? इसका एक छोटा सा उदाहरण देवास राऊ 42 किमी. 5 लेन रोड पहले से ही सीमेंट कांक्रीट का बना हुआ है और यातायात का दबाव भी कोई खास नहीं था, इसके विपरीत इस विपरीत इस रा.रा. 3 को सिक्स लेन बनाने के लिए रु. 450 करोड़ में गायत्री कंस्ट्रक्शन को बिना बनाये ही टोल, ठेके को प्रारंभ करने के साथ ही वसूल करने का अधिकार देकर शुरुआत करना दी गई, उस हरामखोर जालसाज गायत्री कंस्ट्रक्शन ने सड़क में बरसात से बने गड्ढों के पेंच सुधारे बिना ही पहले टोल बूथ बनाकर मांगलिया पर वसूल शुरू करने की तैयारी कर ली थी। वह तो जनता के दबाव और उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण टोल वसूलने से वंचित हो गया। इस पर भी ठेकेदार ने पेंच सुधार कर थिगड़े लगाये वह भ मात्र 5% हिस्से अर्थात लगभग 2 किमी. पर खर्च किया मात्र 3 से रु. 5 लाख, मांगलिया बाईपास से टोल बूथ तक मात्र 400 मी. में न तो खुदाई की गई, न बोलर बिधाये गये 6'' मिट्टी साफ कर गिट्टी बिछा कर टोल बूथ तक 4 लेन बना दिया गया। खर्च हुआ मात्र अधिकतम रु. 5 लाख। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता का एक छोटा सा उदाहरण।

वैसे तो पूरा रा.रा. क्र. 3 बेंच दिया गया है। देवास से मवसी तक वर्षभर गुजरने के बाद कोई काम अभी तक इस 35 किमी. में नहीं किया गया, वही हाल इस रा.रा. लूट प्राधिकरण का इंदौर झाबुआ मार्ग पर भी है। इसके हरामखोर ठेकेदार आईटीआर ने 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य पिछले वर्ष अप्रैल से शुरू तो कर दिया था, परन्तु मूल सड़क पर इंदौर से धार तक न करने के कारण न्यायालयों में याचिकाएं तक लगा दी गई, परन्तु उस शूकर ने पुरानी सड़क पर रखरखा की अपेक्षा टोल शुरू कर वसूली के लालच में पहले नई सड़क बनाने में लगा हुआ है। यही हाल पूरे म.प्र. के रा.रा. राजमार्गों का है।

वही हाल इंदौर से सेंधवा तक रा.रा.क्र. 3 जो कि नया बनाया गया था उस पर टोल लगाया गया, परन्तु वर्तमान मं उसकी स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके विपरीत टोल टैक्स हर वर्ष 10% की दर से बढ़ाया जा रहा है।

वास्तविकता में पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग डकैतों को सौंप दिया गया है। जो रु. 1 लगाकर 90% कमायेंगे अगले बीस वर्ष तक वसूलेंगे जो कि उनके बीस वर्ष में कुल विनियोग को 3000 गुना कमाई देगा, वह भी टैक्स फ्री, अर्थात जनता से सारी वसूली और डकैती में इनके सबके कमीशन भी 50% तक मिलता रहेगा जो इनकी वर्तमान के साथ भावी पीढ़ियों की व्यवस्था कर देगा।

जहां तक पेट्रोल की तेजी से बढ़ती कीमतों का सवाल है तो इसकी भी हकीकत है मोटा कमीशन और केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर दोनों हाथों से कमा रही है। जहां तक अनुदान का सवाल है तो इसके विपरीत 40% करों का भारी भरकम बोझ भी लादा हुआ है। उस पर भी शिक्षा 2% सेस, 0.5% उच्च शिक्षा, 2% सड़क से भी वसूला जा रहा है, सड़कों पर 2% के मान से लाखों करोड़ रु. सड़क निधि में इकट्ठा हो रहा है। हजारों कराड़ की बात बेमानी है। उस पर भी राजमार्गों से टोल टैक्स क माध्यम से हर किमी. पर 50 पै से 1 रु. व रु.2 टोल टैक्स वसूली और प्रति ली. रु. 44 का केंद्रीय और रु. 24 का राज्यों के कर वसूले जाते हैं। इसके 0.5% कुल गाड़ी की कीमत रोड टैक्स पंजीयन पर भी वसूला जाता है। कारों की कीमत में लगभग सभी प्रकार के 150% टैक्स जिसमें कस्टम ड्यूटी, राज्य और केंद्र का विक्रय कर भी शामिल है। जिसमें कच्चे माल का भी टैक्स जुड़ा है। आखिर जनता को हर कदम कितना और कब तक लूटा जायेगा।

दो वर्ष बाद सड़कों की हालत क्या होगी ये पुराने राज्य के बीओटी और केंद्रीय रा.रा. के बीओटी पर ही सामने आ जायेगी।सूचना के अधिकार में क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र दिया था, परन्तु जालसाज शूकरों की वही जालसाजी पूरी नीतियां जवाब न देने के हथकंडे अपनाये गये। भोपाल के प्रादेशिक कार्यालय में अपील की गई तो वहां इनसे बड़े शूकर बैठे थे, उनके पत्र से तो यह स्पष्ट लगा कि वो महाप्रबंधक नहीं वरन् राष्ट्रीय राजमार्ग उसकी बपौती है। जालसाज हरामखोर अपनी काली करतूतों का चिट्ठा कैसे सौंप दें। निष्कर्ष यह है कि जनता को ही सड़कों पर उतर कर इन डकैतों को गुर्जर आंदोलन की तरह आंदोलन कर अपने अधिकारों की सुरक्षा करना पड़ेगी।

साप्ताहिक समय माया

चीन की तरह भारत में भी पूरे देश में हो

हर मोहल्ले में हो जिम, इंडोर आउट डोर खेल व्यवस्था

अगले 5 वर्षों में ही स्वस्थ, स्फूर्त, ताजगी भरा होगा पूरा देश

विश्व में आबादी में हमारे देश का दूसरा स्थान है। पर ऑलोपिंक में हमारा स्थान चीन, जापान, रुस और अमेरिका जैसे देशों के बाद भी नहीं आता। आखिर क्यों? बेशक भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इसके विपरीत हमारी 60 वर्षों से ज्यादा की आजादी के बाद भी हमने इसके लिए कोई ठोस नीति ही तैयार ही नहीं की। वर्तमान में पूरे देश में सैकड़ों 10 लाख से ज्यादा की आबादी के नगरों में संपूर्ण सुसज्जित न तो इंडोर स्टेडियम है, न ही आउटडोर स्टेडियम और खेल मैदानों की व्यवस्था की है। तो फिर 10000 से 1 लाख की आबादी के 1 लाख से ज्यादा तहसील स्तर के नगरों में इन आंतरिक और बाह्य खेल मैदानों की व्यवस्था की कल्पना ही बेकार है। स्वाभाविक है 20 करोड़ से ज्यादा आबादी तो अधिकांश खेलों को केवल टीवी पर ही देख पाई है। जब खेल होते हुए सामने देख ही नहीं पाएंगे तो खेलेंगे क्या खाक दूसरी ओर हमारे देश में 5 से 15 वर्ष की आय के 25 प्रतिशत बच्चों को अभी भी मां बाप के साथ घरेलु और जीवन यापन के व्यवस्थाओं में ग्रामीण बच्चें मुश्किल से ही स्कूलों तक पहुंच पाते है। सरकारी स्कूलों के भोजन की व्यवस्था भले ही पंचायतों से लेकर प्रदेश और देश की राजधानी तक में कागजों पर ही सिमटी हुई है। मध्यान्ह भोजन का अनाज सरपंच और ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षक ही मिलकर आधे से ज्यादा उकार रहे है। इस मध्यान्ह भोजन का एक कड़वा सच यह भी है। कि इस मद में अधिकतम आबंटन के लिए सरपंच और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने मिलकर कुल स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या से दुगुने बच्चों की संख्या, नाम, माता-पिता के नाम उनके हाजिरी पंजी में चढ़ा रखे है। ताकि उनके भोजन के नाम से प्राप्त धन, अनाज व अन्य सामग्रियों का आबंटन में बंदर बांट कर सके। पिछले 5 वर्षों से सबसे सर्वोच्च न्यायाय ने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के आदेश दिए है। शिक्षकों, प्राचार्यों और गांवों के सरपंचों शहरीय आबादी में वार्डो और परिषद के सदस्यों को कमाई और भ्रष्टाचार का नया स्त्रोत मिल गया है। वेशक ग्रामीण और शहरीय सरकारी स्कूलों में 20 से 25 प्रतिशत विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई है। यदि इन सभी बच्चों को पर्याप्त खेल की सुविधाएं और अच्छे खेल शिक्षक भी मिल जाए तो स्वाभाविक है हमारा प्रदर्शन खेलों में पदकों की बढ़त के साथ बेहतर होता जाएगा। चीन ने अपने देश में खेलों का प्रदर्शन सुधारने के लिए जिस तरह से हर गांव, नगरों के हर गली, मोहल्लों में सार्वजनिक जिम, व्यायाम केन्द्रों को खोलने के साथ ही मुफ्त में खेले के लिए आंतरिक और बाह्य खेलों को खेलनेके लिए सार्वजनिक केन्द्र खोल कर बच्चों, युवाओं के साथ प्रौढ़ और बुजुर्ग पीढ़ी को भी आकर्षित कर, जनता के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों को भी घटाया दूसरी तरफ आमजन को स्वास्थ्य और स्फूर्त बना कर अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी औद्योगिकी करण में भी ताजगी भरा माहौल पैदा कर विश्व में स्थापित कर दिया। भारत में भी न केवल खेलों के विकास वरन स्वास्थ्य, स्फूर्त भारत की आबादी के लिए हमें भी चीन से यह सबक सीख लेना चाहिए। हमें भी हर नई विकसित होती, बस्ती कालोनी, नगर, व हर 10000 से ज्यादा बड़ी आबादी के क्षेत्र नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के नियमों और कानूनों में भी यह व्यवस्था की जानी चाहिए।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भाजपाई मुख्यमंत्री का इतिहास है सत्र समय पूर्व समापन,

बजट सत्र 11-12 समय पूर्व ही होगा समाप्त

भ्रष्ट, अपने ही कुकर्मों से भयभीत हो, विपक्ष का सामना करने से बेहतर, समय पूर्व ही सत्र समापन कर देते हैं

भोपाल। म.प्र. में भाजपा की सरकार का मुख्यमंत्री चाहे वर्तमान नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गोर हो, या वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान दोनों ने ही 23 में से मात्र 6 सत्र पूरे किये अर्थात 75% सत्र 17 सत्र समय पूर्व ही बहाने बनाकर समाप्त कर दिए गए।

12वीं विधानसभा का गठन 5/12/03 को किया गया, जिसकी समाप्ति नवम्बर 8 में हो गई इसे 15 सत्र संपन्न हुए जिसमें से मात्र 3 सत्र ही पूरे हुए अर्थात 80% सत्र समय पूर्व ही समाप्त कर दिये गये, जिसमें पहले दो सत्र उमा भारती के कार्यकाल के थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए सुश्री उमा भारती पूरे किये वादे में मुख्यमंत्री बाबूलाल गोर ने पहला सत्र पूरा किया बाद के 12 सत्र जिसमें 272 बैठकें होनी थीं; कोई भी पूरे नहीं किये गये उसमें मात्र 158 बैठकें ही हो सकीं, जिसके पीछे एक मात्र कारण रहा कि जनता को भविष्य की शब्दों की मीठी रेवड़ी बांटकर सत्ता तो हथिया ली परन्तु सत्ता प्राप्त कर ये भी न केवल ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ ही काम नहीं कर पाए वरन इनका प्रबंधन भी भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण बेशर्मी पूर्ण रहा, जिसके बारे में ये विपक्ष के तेवरों का सामना करने की स्थिति में ही नहीं थे इसलिए 12 सत्रों का समय पूर्व समाप्ति कर दी गई।

13वीं विधानसभा में भी भाजपा का ये मुख्यमंत्री जनता के सामने भले ही भोली और मीठी बातें कर आश्वासनों के पुलिंदे थमाकर वाहवाही लूट लेता हो, इसके विपरीत इस विधानसभा के 8 सत्रों में से मात्र 3 ही सत्रों में लगभग पूरी बैठकें हुई; जबकि पहले एक दिन तो श्रद्धांजलि और दूसरी कार्यवाहियों में पूरे कर दिए जाते हैं। 13वीं, विधानसभा के आधे सत्र 8 पूरे हो चुके हैं जिसमें 63 बैठकें होना थीं मात्र 66 बैठकें हुईं अवश्य पर 8 बैठकें पहले 16 दिन श्रद्धांजलियों और अन्रू औपचारिकताओं में ही बर्बाद चले गये। म.प्र. का बजट सत्र जो 21फरवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल 2011 तक चलना है, जिसे होली के पूर्व 18 माच्र तक ही समाप्त कर दिया जाएगा और ज्यादा हल्ला मचा तो 25 मार्च तक खींचा जा सकता है। जिसकी संभावना नगण्य है। हां समय माया के इस लेख के बाद हो सकता है बेशर्मी से बचने के लिए 1 अप्रैल तक खींचा जाए। यहां भी मात्र समय पूर्व सत्रावसान के पीछे भी वही भ्रष्टाचार, प्रबंधन की असफलताओं, बढ़ते अपराध, गिरती जनसुरक्षा, किसानों की आत्महत्याओं, किसानों के मुआवजे के मुद्दों के सामने सरकार, उसके मंत्री टिक नहीं पायेंगे और किसी भी कारणों का बहाना लेकर सत्रावसन कर दिया जाएगा।

म.प्र. शासन-अंधे पीसे कुत्ते खायें

भ्रष्टों को क्रीम, मेहनतकशों को नीम

जसं.वि. में सचिव प्रजापति, लोस्वायां. में डामोर, लोनिवि में शुक्ला, तीनों महाभ्रष्ट गैर कानूनी तरीके से वसूली के लिए बैठाये

म.प्र. की सत्ता विशुद्ध नयन सुखों द्वारा चलाई जा रही है। पूरे प्रदेश के हर विभाग में सभी बड़े भ्रष्टों को क्रीम खिलाई जा रही है और मेहनतकशों को उनकी मेहनत के बदले कड़वी, हर कदम विसंगतियों से परेशानियों, मुसीबतों, स्थानांतरण, संलग्नक, निलंबित पदोन्नतियां, की नीम की कड़वी खुराक पिलाई जा रही है। म.प्र. के जल संसाधन विभाग को ही लें, यहां पूर्व में बैठे महाजालसाज और भ्रष्ट जिसका जाति और मूलनिवासी प्रमाण पत्र फर्जी है जिसे समय माया ने दस्तावेजों के साथ प्रकाशित किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि इस प्रमुख अभियंता ने जो होशंगाबाद जिले का रहने वाला है परन्तु जातिप्रमाण पत्र छतरपुर का प्रस्तुत कर इसने आरक्षित वर्ग से नौकरी प्राप्त की और 30-32 वर्षों से पदोन्नति की आस में बैठे इसके साथ नियुक्त हुए सहायक यंत्री अभी भी उसी पद पर बैठे हैं परन्तु फर्जी जाति के दम पर यह प्रमुख अभियंता पद पर विराजमान हो गया। साथ ही यह भी भ्रष्ट प्रधान सचिव अरविन्द जोशी जो आयकर छापे में रुपए 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी और रुपए 350 करोड़ की अन्य संपत्तियों के साथ पकड़ा गया था और म.प्र. जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव था ने इसी प्रजापति के माध्यम से म.प्र. जल संसाधन में अरबों रुपए की डकैती डाली थी उसकी आयकर जांच और लोकायुक्त जांच में भी इसको बचाया गया था जबकि यही प्रजापति उसके साथ मिलकर लूटो और लुटाओ में शामिल था। वर्तमान प्रधान सचिव ने इसके भ्रष्टाचार और जालसाजियों के चलते व अपने मातहतों के साथ बहुत बत्तमीज तरीके से उन्हें लताड़ने और वसूली करने के कारण प्रमुख अभियंता पद से हटा दिया था व मंत्रालय में अटैच कर दिया गया था, भाजपा सरकार के भ्रष्ट शिवराज और उसके मुख्य सचिव अवनिवैश्य ने मोटा धन डकारकर उसी प्रजापति को म.प्र. जल संसाधन को निम्न पत्र के आदेश से सचिव नियुक्त कर दिया गया है। जबकि प्रजापति के फर्जी जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र की जांच चल रही है, बेशक यहां बैठे महाभ्रष्ट जालसाज ज.सं. मंत्री जयंत मधैया ने भी इसे सचिव बनाने में रुपए 2 से 5 करोड़ वसूले होंगे।

इसे मुख्य सचिव अवनिवैश्य ने सचिव शायद इसीलिए ही बनाया है कि रुपए 700 करोड के केंद्र सरकार के बुंदेलखंड पैकेज से म.प्र. जल संसाधन की हिस्से में आने वाले रुपए 100 से 150 करोड़ में से आसानी से 25 से 50% हजम किया जा सके, ताकि मु.स. को भी रुपए 10-20 करोड़ मिल सके अन्यथा क्या कारण था कि इस जालसाज को विभाग का सचिव नियुक्त कर दिया गया।

यही हाल म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के प्रमुख अभियंता पद की कमान संभाले 5 हत्याओं के जुर्म से धन और जालसाजी से बरी हुए सैकड़ों करोड़ की खरीदी में घोटाले अकेले इंदौर में मुख्य अभियंता के पद पर बैठकर 21 संभागों की खरीदी, आवंटन में से हर वर्ष रुपए 50 से 100 करोड़ डकारने वाले, जिसकी लोकायुक्त जांच के मामले में इंदौर उच्चन्यायालय से पिछले तीन वर्ष से कानूनी दांव पेंचों में स्थगन को पैसे के दम पर उलझाकर प्रमुख सचिव आर.के. स्वाई, लो. स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गौरीशंकर बिसेन जो भ्रष्टाचार के धन के साथ ही सुरा-सुंदरी के शौकीन हैं। इतने सारे भ्रष्टाचारों के चलते भी प्रमुख अभियंता पद पर जीएस डामोर को न केवल पदोन्नत कर दिया और इन जांचों के चलते प्रमुख अभियंता पद से एसके सक्सेना के सेवा निवृत्ति के बाद प्रभारी प्रमुख अभियंता पद पर सुशोभित कर दिया। पिछले 5 माह से प्रमुख अभियंता पद के लिए उसे ज्यादा बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली गई परन्तु जान बूझकर लाइन में बैठे मुख्य अभियंताओं को प्रमुख अभियंता के पद पर स्थाई नियुक्ति के मामले में टाला जा रहा है। दूसरी ओर एक वरिष्ठ मुख्य अभियंता को जिसकी सेवा निवृत्ति 31/1/2011 को होना थी, 23/1/11 को प्रमुख अभियंत्रकी योग्य मानकर 27/1/11

को प्रमुख अभियंता घोषित कर 31/1/11 को सेवानिवृत्त कर दिया, अब स्वाभाविक है कि इस सारे खेल का सूत्रधार प्रभारी प्रमुख अभियंता जीएस डामोर पूरे प्रदेश के बजट में से जो लगभग रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा का है न्यूनतम 20 से 25% डकार जाएगा 31/3/11 समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसके बैठते ही सारे भ्रष्टों की बांछे खिल गईं। दूसरी ओर इस हरामखोर जालसाज ने चारो तरफ ऐसी जमावट कर ऐसे बुद्धिहीन नालायक अधिकारियों को बैठा दिया ताकि यह प्र.भ. डामोर जो कहे उसे वो आंख मींच कर दें। अब इंदौर वृत्त में ही लें यहां बैठा अधीक्षण यंत्री सोलंकी ऊपर का भी खाली है। यहां बैठा महाभ्रष्ट मक्कार स्टॉफ जिसमें नागर जैसे अधीक्षक इसे जैसा नचाते हैं वैसे ही ये नाचता है, बाकी ऊपर का आदेश जैसा मिलता है करता चलता है। कौन सा कानून, कैसा कानून, इसका एक उदाहरण इंदौर संभाग में बैठा का.अ. अहिरवार ने 27-28 जन 11 को कुछ 2 से 5 लाख रुपए के 4-5 टेंडर खोले किसी में भी अर्नेस्ट मनी की एफडी नहीं थी सारे टेंडर खोले गये, ऐसे टेंडर्स पिछले फरवरी 10 से वर्तमान तक लिए व खोले जा रहे हैं पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है, सरकारी पैसा लूटों और लुटाओ।

यही हाल यहां बैठे इंदौर-उज्जैन संभाग के जिलों 21 संभागों में हर वर्ष रुपए 500 करोड़ से ज्यादा की खरीदी की जाती है। यहां बैठे मुख्य अभियंता भी इस जी.एस. डामोर की कठपुतली हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मु.अ. संकुले निहायत निकंमा, बुद्धिहीन है डामोर जैसे धूर्त भी यही चाहते हैं कि पूरे प्रदेशभर में ऊंचे पदों पर बुद्धिहीन अधिकारियों को बैठाकर आंख मींचकर वसूली की जाए; इसलिए सूचना के अधिकार में पत्र देने पर यहां बैठे धूर्त फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर कार्यवाही करने की अपेक्षा अजय दाहिमा औपचारिकताएं पूर्ण करता है। जिससे इंदौर यांत्रिकीय विभाग में बैठकर सन 2003 से 2008 तक बैठकर रुपए 50 करोड़ से ज्यादा का धन विभिन्न गैर कानूनी कार्यों से डकारा। सूचना के अधिकार में कैसे जानकारी देगा।

यहां पर एक अधीक्षण यंत्री सी.के. सिंग भी संचालक हैं। चूंकि थोड़ी बहुत बुद्धि का उपयोग करना जानते थरे इसलिए इस बंदे को न तो ऑफिस में बैठने की जगह दी गई और न ही कोई काम मात्र इसलिए ही कि वो बुद्धि का उपयोग और कानून की बात करता है। यह भी डामोर की भ्रष्ट, जालसाज और आपराधिक मानसिकता का उदाहरण है कि जिसे सरकार रुपए 40 से 50 हजार वेतन दे रही है। उससे डामोर इसलिये काम ले व दे नहीं रहा ताकि इस हरामखोर का पूरे प्रदेश में कागजों पर काम करवाकर मै। दान में खुली लूट और डकैती चलती रहे; ये है शिव और अवनि की सरकार जहां भ्रष्टाचार में डूबे अंधों को जन धन की बर्बादी नहीं दिख रही। इस विभाग में पूरी कार्यप्रणाली ध्वस्त होने के कगार पर आ गई है। ये है भ्रष्टाचार मुक्त शिव सरकार, जहां भ्रष्टों को पाला पोसा और सैकड़ों अपराध और भ्रष्टाचार करने के बाद भी प्रमुख अभियंता पद पर बैठा दिये गये, क्योंकि इस प्रमुख अभियंता डामोर के टुकड़ों पर प्रधान सचिव आर.के. स्वाई, मंत्री बिसेन न केवल पलते हैं वरन् यह धूर्त उनकी रोटी ओर लंगोटी की भी व्यवस्था करता हैं।

प्रमुख विस्तार पर लोक निर्माण विभाग

भ्रष्टाचार की हरियाली के अंधे प्रशासन ने पूरे प्रदेश के हर विभाग में भ्रष्टाचार से धन नोचने वालों को अपनी कमाई के लिए हर प्रकार का संरक्षण दिया। यहां तक कि सेवा निवृत्ति के बाद भी सेवा विस्तार देकर वसूली के लिये लोक निर्माण जैसे विभाग में भी प्रमुख अभियंता शैलेन्द्र शुक्ला, जिसे सुंदरी नृत्य दर्शन के बिना नींद नहीं आती; के भ्रष्टाचार के किस्से पिछले 6 वर्षों से लगातार जनहित में प्रकाशित किये हैं; जो विद्युत यांत्रिकीय से इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हैद्ध को मात्र भ्रष्टाचार से लूट-खसोट और वसूली के लिये ही प्रमुख अभियंता, जो कि सिविल इंजीनियरिंग उत्तीर्ण न होने के बाद भी पद नवाजा गया, सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसे विस्तार देकर पूरे लोक निर्माण विभाग को भ्रष्टाचार से पाट दिया गया। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार रुपए 5 करोड़ खर्च कर उसे विस्तार मुख्य अभियंताओं के पद खाली होने के कारण दे दिया गया, अब जबकि उसने 4-5 बार पुनः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक को टाला गया ताकि मुख्य अभियंताओं की पदोन्नतियों के अभाव में जमा रह कर 2010-11 के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के धन आवंटन में से वह 10% हिस्सा डकार सके; इसलिए चारों तरफ यह भी ऐसे भ्रष्टों, नाकाराओं की टीम के अभियंताओं से धन लेकर उन्हें बड़े आवंटन और काम वाले पदों पर बैठा रहा है। इसका एक उदाहरण भ्रष्ट और फर्जी प्रमाण पत्रों के दम पर बने का.अ. ए.पी. राणे को ही लें यह तीन वर्ष से ज्यादा समय से इंदौर संभाग क्र.-2 में बैठा था, यह वही अभियंता है जिस पर अंबेडकर भवन महू निर्माण में लोकायुक्त जांच थी, जिसने देवास में अधिकांश सड़कों में 30 से 40% अपने भिंड से बुलाये ठेकेदारों से काम करवाकर डकारा, यही हाल इसने धार संभाग में रहकर भी किया। लेबड़-रतलाम सड़क पर पेंचवर्क में भी रुपए 50 लाख के घोटाले के मामले इसकी बहुत शिकायतें की गई थीं पर सब ले-देकर खत्म कर दी गई। धार और इंदौर से खरीदी में भी मोटा कमीशन डकारा गया। इंदौर संभाग दो में बैठकर इसके साथ मुख्य अभियंता एम.पी. सिंग ने खूब समय वृद्धि और महंगाई वृद्धि में ठेकेदारों से वसूली की गई। अभी भी इंदौर सीाग क्र.-1 में आने के लिए भी प्रमुख अभियंता शैलेन्द्र शुक्ला को रुपए 50 लाख दिये जाने के समाचार हैं। साथ ही यही कारण है कि जब इसका स्थानांतरण संभाग क्र.-1 में कर दिया गया तो इसे संभाग क्र.-2 से प्रभार लेकर दूसरे को इसीलिए देने के आदेश नहीं किये जा रहे; ताकि संभाग -2 के 31/3/11 तक के आवंटन और उसके कार्यों में से 25 से 40% कमीशन जो लगभग रुपए 1 करोड़ से ज्यादा होता है हाथ से निकल जाएगा; इसीलिए प्रभारी प्रमुख अभियंता जो दोनों हाथों से हर आवंटन में 5 से 10% राशि वसूल कर ही उन्हीं संभागों का आवंटन जारी करता है जो नहीं देते उन्हें किसी न किसी बहाने अटकाकर रख कर परेशान किया जाता है।

पूरे म.प्र. में शासन में बैठे, अपनी अंधी कमाई के लिए चारों तरफ हर विभाग में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए भ्रष्टों को सिरमौर बनाकर दोनों हाथों से वसूली कर रहे हैं। चारों तरफ चाहे वो ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, पंचायत, ग्रामीण विकास, आदिम जाति कल्याण, वाणिज्यकर आबकारी, कृषि, उद्यानिकी, उद्योग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंजीयन, पुलिस, खनिज, राजस्व, परिवहन कोषालय, शिक्षा, वन, प्रदूषण, पशु चिकित्सा, डेयरी, नर्मदा घाटी आदि में भारी भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों का जमावड़ा है। जितने भ्रष्ट हैं उतने आगे हैं जो सिद्ध करता है, कि अंधे पीस रहे हैं और अधिकारी जीम रहे हैं।

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु/ 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इंदौर से मुद्रित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालयः 0731- 2530859, मो. 9300755803